राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 05 अगस्त 2026 वर्ष-9,अंक-184 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

'चढ़ावा चोरी' को लेकर संसद में संग्राम

विपक्ष का भारी हंगामा,खड़गे बोले-ईडी कहां है

रिजिजू ने कहा-विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस दौरान टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही दिन में दो बार स्थगित हुई। 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के आधे घंटे के भीतर स्थगित भी हो गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन 20 मिनट ही चल पाई। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा- राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था।

वित्त मंत्री सीतारमन ने शोर-शराबे के बीच बिल पेश किया

दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। पीठासीन दिलीप सैकिया ने इन सांसदों को नारे न लगाने और बैठ जाने के लिए कहा लेकिन वे नहीं माने। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टैक्सेशन एंड अदर्स लॉ (संशोधन) बिल पेश किया। बिहार और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अब साफ है कि जनता भाजपा से ऊब चुकी है।

यूपी विधानसभा में पोस्टर दिखाने पर जमकर बवाल

- सपा विधायक बाहर निकाले गए,सीएम का हमला

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी विधानमंडल में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सपा और कांग्रेस ने इसको लेकर सदन में नारेबाजी की। इस दौरान जैसे ही सीएम योगी बोलने के लिए खड़े हुए, सपा विधायक सचिन यादव ने हाथ में एक पोस्टर लहराया जिसमें सीएम की फोटो के साथ चढ़ावा चोरी को लेकर कई सवाल पूछे गए थे। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया। इस दौरान सपा की महिला विधायकों ने हंगामा किया।

चढ़ावा चोरी का साधु-संतों से कोई मतलब नहीं

सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो भी लोग पकड़े गए हैं, उनका भाजपा और साधु-संतों से कोई लेना देना नहीं। इसके बावजूद विपक्ष के नेता सनातन धर्म पर अनावश्यक लांछन लगा रहे हैं। ये लोग सत्य को दबाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग सदन में चर्चा से भागना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से जो एजेंडा हाउस द्वारा तय किया गया था,उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हों,उन सभी पर विरोधी दल के लोगो ने कोई रुचि नही ली।

बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद हलचल तेज

- पीएम मोदी से मिले नीतिश और ललन सिंह, संजय झा भी थे साथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की मुलाकात हुई है। भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिश ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में पीएम से उनके चैंबर में मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। नीतिश ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। हालांकि, बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद यह मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और नीतिश कुमार ने एक दिन पहले जारी हुए

पटना शहर की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजों पर भी चर्चा की। हालांकि, भाजपा या जदयू में किसी भी दल की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

पीके ने भाजपा को बड़े अंतर से हराया

भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने 19 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा के कैंडीडेट नीरज कुमार सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी, जो लगातार पांच बार यहां से विधायक रहे। नितिन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया था, जिसके बाद मार्च 2026 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था।

एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी

- किसी के कान का पर्दा फटा, किसी का कंधा हुआ चोटिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। एअर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट एआई 2379 मंगलवार को टर्बुलेंस (तेज हवा के झटकों) में फंस गई। तेज झटकों के कारण फ्लाइट हिलने लगी और अचानक नीचे आने लगी। हालांकि, पायलट ने स्थिति संभाली और फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दिया। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हादसे में विमान में सवार 12 लोग घायल हुए हैं। इनमें यात्री और क्रू मेंबर्स शामिल हैं। घायलों को दिल्ली एयरपोर्ट के

मेडिकल सेंटर में जांच और इलाज के लिए भेजा गया है। एअर इंडिया ने पहले बताया था कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। घटना की जांच की जा रही है। टर्बुलेंस के बाद फ्लाइट की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें प्लेन की सीलिंग के पैनल में दरारें दिखीं। टर्बुलेंस का मतलब है हवा का बहाव अचानक बदल जाना, जिससे विमान को झटके लगने लगते हैं।

इस दौरान विमान कुछ समय के लिए ऊपर-नीचे या दाएं-बाएं हिल सकता है और कभी-कभी कुछ फीट नीचे भी आ जाता है। इसी वजह से यात्रियों को लगता है कि विमान गिर रहा है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। टर्बुलेंस को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ऊबड़-खाबड़ सड़क पर चलती कार अचानक हिलने लगती है। कुछ टर्बुलेंस हल्के होते हैं, जबकि कुछ ज्यादा तेज हो सकते हैं।

भारतीय एजेंट्स ने हमारे 30 लोगों को मारा

- आतंकी बोला-पेशावर से रावलपिंडी तक हमले किए
- लश्कर ने कहा-पीओके में भी चैन से नहीं रहने दिया

इस्लामाबाद (एजेंसी)। इस्लामाबाद में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी रिजवान हनीफ ने दावा किया है कि पिछले तीन-चार साल में उनके संगठन के 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसके मुताबिक ये हमले पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावलकोट और मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने किए। उसने आरोप लगाया कि ये हमलावर भारतीय एजेंट्स थे। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें हनीफ कहता है, हमारे लोगों को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आजाद कश्मीर में अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने एजेंट्स के जरिए उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया।

40 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा का गठन- लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना 1987 में पाकिस्तान में हुई थी। यह संगठन सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान बने जिहादी नेटवर्क से निकला था। ओसामा बिन लादेन के मेंटर माने जाने वाले अब्दुल्ला अज्जाम और उसके दो

साथियों ने मिलकर मरकज-अद-दावा-वल-इरशाद नाम के धार्मिक संगठन की स्थापना की। मिलिटेंट विंग बाद में लश्कर-ए-तैयबा कहलाया।

पाकिस्तान पहले भी भारत पर ऐसे आरोप लगा चुका

पाकिस्तान पहले भी देश में आतंकियों की हत्याओं के लिए भारत पर आरोप लगाता रहा है। जनवरी 2024 में तत्कालीन विदेश सचिव मुहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने दावा किया था कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान में सीमा पार टारगेट किलिंग में शामिल हैं। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद अप्रैल 2024 में ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2020 के बाद पाकिस्तान में करीब 20 आतंकियों और उग्रवादियों की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े लोग भी शामिल बताए गए। रिपोर्ट में पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

तमिलनाडु के नेता विपक्ष उदयनिधि गिरफ्तार, फिर रिहा

- एक्ट्रेस तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली में उदयनिधि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान भीड़ से तृषा, तृषा के नारे लगे। आरोप है कि इस पर उन्होंने कहा, पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को डबल मीनिंग और महिलाओं का अपमान करने वाली बताया। इसी आरोप के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

डीएमके नेता बोले-उदयनिधि ने किसी का अपमान नहीं किया- डीएमके नेता टीकेएस इलांगोवन ने कहा कि मैंने पूरी स्पीच सुनी। जैसा कहा जा रहा है, भाषण में वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने (उदयनिधि) केवल सीएम की नाकामियां गिनाईं।

पटना की सड़कों पर एक बार फिर उतरा वाटर कैनन

एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन हिरासत में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष

पटना (एजेंसी)। छात्रों पर हुई फायरिंग और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए हमले के विरोध में पटना की सड़कों पर भारी हंगामा देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आयकर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति उस समय बेकाबू हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। छात्र आंदोलन के दौरान हुई फायरिंग की घटना और दिल्ली में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले के विरोध में यह मार्च निकाला गया था।

मदरसे में पढ़ने वालों की सोच आतंकवादियों जैसी है:केशव

मौर्य बोले-ये नहीं बोलते भारत माता की जय

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसा और यहां पढ़ने वालों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मदरसे में पढ़ने वालों की मानसिकता एक आतंकवादी जैसी होती है। वह पहले भी यह बात बोल चुके हैं। मौर्य ने यह भी दावा किया कि यूपी में बीजेपी 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मदरसे को लेकर दिए गए बयान के सपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने मौर्य पर निशाना साधा है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में केशव मौर्य ने कहा-मदरसी शिक्षा जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता।

मदरसे आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री- केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले बोले थे कि मदरसा चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का, देखा जाए तो वे अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री हैं। मदरसों का मुख्य चरित्र और उनका मकसद आतंकवाद को बढ़ावा देना ही है। गौरतलब है कि योगी सरकार मदरसों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा कामिल (स्नातक) और फाजिल (परास्नातक) की डिग्रियों पर पूरी तरह रोक लगाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मदरसों में अब केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई हो पाएगी। दरअसल, 5 नवंबर 2024 को अंजुम कादरी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की गाइडलाइंस का पालन किए चलाए जा रहे उच्च शिक्षा के कोर्स बंद किए जाएं। इसी आधार पर राज्य सरकार यह कदम उठाने जा रही है।

पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

- रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर रेकी कर रहे थे आरोपी
- 9 लोग हुए गिरफ्तार,पेट्रोल बम बरामद; विदेशी हैंडलरों से संपर्क

अमृतसर (एजेंसी)। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से संचालित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 4 नाबालिगों समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और पेट्रोल से भरी 4 बोतलें, जिन्हें बम के रूप में इस्तेमाल किया जाना था बरामद की गई हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे आईएसआई हैंडलरों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार इन युवकों को आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्हें सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी करने,

अवैध हथियार जुटाने और पंजाब में शांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने जैसे कार्य सौंपे गए थे। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इन कैमरों से रिकॉर्ड की गई फुटेज कथित तौर पर विदेशी आईएसआई हैंडलरों को भेजी जा रही थी, ताकि नजर रखी जा सके।

अन्य सदस्यों की पहचान

अमृतसर के मोहकमपुरा, एयरपोर्ट और सी-डिवीजन थाना में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। साथ ही इसके आगे और पीछे जुड़े संपर्कों, फंडिंग के स्रोत व विदेश से मिलने वाली आर्थिक मदद की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या गिरफ्तार आरोपी किसी अन्य आतंकी साजिश या घटना में भी शामिल रहे हैं। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि करीब एक महीने पहले अमृतसर-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर एक ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन) पोल पर सीसीटीवी कैमरा मिला था। कैमरे को बिजली आपूर्ति देने के लिए वहां सोलर पैनल भी लगाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को एक सिम कार्ड मिला है।

केजरीवाल ने पीएम आवास तक निकाला मार्च, दिया धरना

- पुलिस ने रोका,फिरोजशाह रोड पर धरने पर बैठे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ई 20 फ्यूल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकला। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं को फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल सहित अन्य एएपी नेता फिरोजशाह रोड पर ही बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। एएपी ने करीब 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ यह मार्च निकाला था। पार्टी का दावा है कि उसने देशभर से 2.30 लाख से ज्यादा लोगों की याचिकाएं जुटाई हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

सौंपना था। मार्च के दौरान केजरीवाल ने कहा कि ई 20 के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं, जिन्हें वे खुद प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं। लेकिन हमें पुलिस ने रोक दिया। हमने सभी चिट्ठियां मोदी जी को भेज दी हैं। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा- हमें उम्मीद है कि पीएम हमसे मिलेंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संसद,कानून और लोकतंत्रः मानसून सत्र 2026 के अंतिम चरण में विधायी जवाबदेही की चुनौती

(लेखक--एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं)

-क्या केवल ध्वनि मत पर्याप्त लोकतांत्रिक संतुष्टि प्रदान करता है? समग्र व्यापक विश्लेषण

पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज, विपक्ष का विरोध मतदान का बहिष्कार और ध्वनि मत से विधेयकों के पारित होने पर लोकतांत्रिक विमर्श

लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल बहुमत में नहीं, बल्कि बहस,संवाद,विपक्ष की भागीदारी, विधेयकों की गहन जांच,मतदान की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही में निहित होती है वैश्विक स्तरपर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय संसद उसकी लोकतांत्रिक आत्मा का सर्वोच्च संस्थागत मंच है। संसद केवल कानून बनाने की इमारत नहीं,बल्कि जनता की आशाओं, समस्याओं असहमतियों और अपेक्षाओं को राष्ट्रीय नीति में बदलने वाली संवैधानिक व्यवस्था है। संसद में सरकार बहुमत के आधार पर शासन करती है,किंतु लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल बहुमत में नहीं,बल्कि बहससंवाद विपक्ष की भागीदारी,विधेयकों की गहन जांच,मतदान की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही में निहित होती है,इसलिए मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ी क़ि संसद का मूल्य केवल इस बात से नहीं आंका जाना चाहिए कि कितने विधेयक पारित हुए,बल्कि इस बात से भी आंका जाना चाहिए कि वे कितनी चर्चा,कितनी जांच और कितनी लोकतांत्रिक भागीदारी के बाद पारित हुए। वर्ष 2026 के मानसून सत्र के अंतिम चरण में पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दे ने संसद के भीतर एक गंभीर राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रश्न खड़ा किया। विपक्ष ने परीक्षा अनियमितताओं,छात्र आंदोलनों और कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा।इसके बाद विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज कराया और कुछ अवसरों पर मतदान की प्रक्रिया का बहिष्कार किया। इसी राजनीतिक तनाव के बीच सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक,2026 संबंधी संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ। तथा इसपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जुलाई 2026 को अपनी स्वीकृति (मंजूरी) दे दी है, और कानून मंत्रालय द्वारा इसी दिन इसकी राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह अब कानून लागू हो चुका है।

साथियों उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार विधेयक पर बहस हुई, लेकिन सदन में तीखी नोकझोंक और व्यवधान के बीच अंतिम स्वीकृति ध्वनि मत से दी गई।बता दे क़ि संसद के मानसून सत्र 2026 में 31 जुलाई तक कम-से- कम 3 प्रमुख विधेयक (1) लोक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम)संशोधन विधेयक,2026 (2) राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 दोनों सदनों से पारित ध्वनि मत (3) जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026,यानें तीनों विधेयक ध्वनि मत से पारित किए गए; इस अवधि में किसी विधेयक पर औपचारिक विभाजन (रिकॉर्डेड वोटिंग) का स्पष्ट मामला सामने नहीं आया। यह घटनाक्रम केवल एक विधेयक के पारित होने का प्रश्न नहीं है। इसके माध्यम से एक बड़ा लोकतांत्रिक प्रश्न सामने आता है, जब किसी कानून का संबंध लाखों विद्यार्थियों के भविष्य, परीक्षा की विश्वसनीयता और युवाओं के विश्वास से हो, तब क्या केवल ध्वनि मत पर्याप्त लोकतांत्रिक संतुष्टि प्रदान करता है? और यदि विपक्ष मतदान का बहिष्कार करता है,तो क्या सरकार की जिम्मेदारी केवल बहुमत के आधार पर कानून पारित करना है,या उसे व्यापक राजनीतिक सहमति और सार्वजनिक विश्वास भी सुनिश्चित करना चाहिए? पेपर लीक केवल परीक्षा की गड़बड़ी नहीं,युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक विश्वास का प्रश्न।

साथियों, सरकार का पक्ष यह रहा कि पेपर लीक जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कानून और त्वरित न्यायिक व्यवस्था आवश्यक है।यह तर्क अपने आप में महत्वपूर्ण है,क्योंकि संगठित परीक्षा अपराधों पर प्रभावी दंड, जांच और समयबद्ध सुनवाई की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।लेकिन लोकतंत्र में कानून की कठोरता के साथ उसकी विश्वसनीयता भी आवश्यक होती है। यदि कानून बनाने की प्रक्रिया में व्यापक चर्चा, संशोधनों पर विचार और विपक्ष की भागीदारी कम दिखाई दे, तो कानून की वैधानिकता तो बनी रहती है, किंतु उसके प्रति राजनीतिक और सामाजिक स्वीकार्यता का प्रश्न उठ सकता है। साथियों बात अगर हम विपक्ष का विरोध और मतदान का बहिष्कार- लोकतांत्रिक अधिकार या संसदीय प्रक्रिया की कमजोरी? इसको समझने की करें तो लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य केवल सरकार की आलोचना करना नहीं है। विपक्ष जनता के उन वर्गों की आवाज भी है जिनकी अपेक्षाएं, शिकायतें या असहमति सरकार की प्राथमिकताओं से अलग हो सकती हैं। संसद में विपक्ष का विरोध, नारेबाजी, बहिर्गमन या मतदान का बहिष्कार राजनीतिक असहमति व्यक्त करने के संसदीय साधन हो सकते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि लगातार व्यवधान और मतदान से दूरी विपक्ष की विधायी भूमिका को कमजोर कर सकती है।पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष ने यह तर्क रखा कि पहले छात्रों के प्रश्नों, आंदोलन और कथित प्रशासनिक कार्रवाई पर स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए। यदि विपक्ष को लगता है कि उसके मुद्दों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, तो विरोध उसकी राजनीतिक रणनीति बन सकता है।

दूसरी ओर, यदि विपक्ष मतदान का बहिष्कार करता है, तो वह विधेयक की धाराओं में संशोधन प्रस्तावित करने, सरकार से स्पष्टीकरण मांगने और रिकॉर्डेड वोट के माध्यम से अपनी स्थिति दर्ज कराने का अवसर भी सीमित कर देता है।इसलिए लोकतांत्रिक जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। सरकार को विपक्ष की बात सुनने और महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि विपक्ष को भी विरोध के साथ विधायी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। लोकतंत्र में केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं; वैकल्पिक सुझाव देना, संशोधन प्रस्तुत करना और मतदान में अपनी स्थिति सटीकता से दर्ज कराना भी आवश्यक है।

साथियों बात अगर हम ध्वनि मत क्या है और इसकी संवैधानिक- संसदीय स्थिति क्या है? इसको समझने की करें तो ध्वनि मत भारतीय संसद की एक मान्य और लंबे समय से प्रचलित संसदीय प्रक्रिया है। इसमें अध्यक्ष या सभापति सदन से पूछते हैं कि प्रस्ताव के पक्ष में कौन है और विरोध में कौन है। सदस्य फ्हाँफ्र या फ्रनहींफ्र कहकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष ध्वनि की तीव्रता के आधार पर निर्णय देते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार हुआ या अस्वीकार। भारतीय संसदीय परंपरा में ध्वनि मत कोई असंवैधानिक या अवैध प्रक्रिया नहीं है; यह सामान्य संसदीय निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है।लेकिन ध्वनि मत की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसमें प्रत्येक सांसद का व्यक्तिगत मतदान रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होता। जनता यह नहीं जान पाती कि किस सांसद ने किसी विधेयक के पक्ष या विरोध में मतदान किया। यदि किसी सदस्य को अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति हो, तो नियमों के अनुसार वह विभाजन अर्थात डिवीज़न की मांग कर सकता है। विभाजन में मतों की गिनती या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्पष्ट परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।यहीं से लोकतांत्रिक बहस शुरू होती है। ध्वनि मत सामान्य और गैर-विवादित मामलों में त्वरित निर्णय का प्रभावी माध्यम हो सकता है। लेकिन जब विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण हो, व्यापक जनहित से जुड़ा हो, राजनीतिक विवाद का विषय बना हो या विपक्ष उसकी धाराओं पर गंभीर आपत्ति कर रहा हो, तब रिकॉर्डेड मतदान लोकतांत्रिक पारदर्शिता को अधिक मजबूत कर सकता है।

साथियों बात अगर हम क्या ध्वनि मत से विधेयक पारित होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है? इसको समझने की करें तो इस प्रश्न का उत्तर केवल फ्हाँफ्र या फ्रनहींफ्र में नहीं दिया जा सकता। ध्वनि मत स्वयं लोकतंत्र-विरोधी नहीं है। संसद के नियमों में इसका स्थान है और अनेक मामलों में यह समय बचाने तथा सर्वसम्मति या स्पष्ट बहुमत वाले निर्णयों के लिए उपयोगी है। यदि सदन में पर्याप्त चर्चा हुई हो, सदस्य अपनी राय रख चुके हों और किसी सदस्य ने विभाजन की मांग न की हो, तो ध्वनि मत से निर्णय को संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत वैध माना जाता है।लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब ध्वनि मत विस्तृत बहस के विकल्प के रूप में दिखाई देने लगे। यदि किसी विधेयक पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई, उसे संसदीय समिति के पास नहीं भेजा गया, विपक्ष की आपत्तियों पर गंभीर विचार नहीं हुआ और अंत में केवल ध्वनि मत से उसे पारित कर दिया गया, तो लोकतांत्रिक गुणवत्ता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।लोकतंत्र में बहुमत सरकार को निर्णय लेने का अधिकार देता है, किंतु बहस की आवश्यकता समाप्त नहीं करता। बहुमत शासन का आधार है; संवाद लोकतंत्र की आत्मा है। इसलिए किसी विधेयक का केवल पारित हो जाना यह प्रमाण नहीं कि उस पर सटीकता से पर्याप्त लोकतांत्रिक विचार-विमर्श हुआ है।

साथियों बात अगर हम पिछले बारह वर्षों में ध्वनि मत से कितने विधेयक पारित हुए? आंकड़ों की चुनौती को समझने की करें तो पिछले बारह वर्षों में ध्वनि मत से पारित विधेयकों की एकल, समेकित और आधिकारिक संख्या सार्वजनिक संसदीय आंकड़ों में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि संसद के विधायी आंकड़े सामान्यतः विधेयकों के प्रस्तुत होने, पारित होने समिति को भेजे जाने और कानून बनने की जानकारी देते हैं,लेकिन प्रत्येक विधेयक के लिए मतदान की पद्धति,ध्वनि मत,मत-विभाजन,इलेक्ट्रॉनिक मतदान या अन्य प्रक्रिया का एक संयुक्त दशकवार आंकड़ा अलग से प्रकाशित नहीं किया जाता।

इसलिए यह कहना कि पिछले बारह वर्षों में ठीक इतने विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए बिना प्रत्येक विधेयक की कार्यवाही और मतदान रिकॉर्ड की जांच के तथ्यात्मक रूप से सुरक्षित नहीं होगा। संसद की वेबसाइट, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तथा विधेयक-वार रिकॉर्ड के आधार पर अलग-अलग गणना की जा सकती है, लेकिन एक आधिकारिक समेकित संख्या उपलब्ध न होने के कारण किसी अनुमानित आंकड़े को अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।फिर भी व्यापक संसदीय प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट है कि पिछले एक दशक में बड़ी संख्या में विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए हैं और कई महत्वपूर्ण कानूनों पर रिकॉर्डेड मतदान नहीं हुआ।

संपादकीय

भाजपा को झटका

विधानसभा के हालिया उपचुनावों के जो परिणाम सामने आए हैं, वे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन लाने वाले कहे जा सकते हैं। बिहार जहां भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार है और पहली बार उसका मुख्यमंत्री बना है, वहां हाईप्रोफाइल बांकीपुर उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़े तो इसको लेकर पार्टी की फिक्र बढ़ना लाजमी ही है। पिछले बिहार विधानसभा चुनावों में नई-नवेली बनी जन सुराज पार्टी यानी जे.एस.पी की करारी हार हुई थी। उस हार से सबक लेकर जेएसपी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ताल ठोककर बांकीपुर उपचुनाव मैदान में उतरे थे। इस तरह प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में अच्छी जीत हासिल करके भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिये चुनाव परिणाम और भी अधिक कष्टदायक होगा, क्योंकि यह पार्टी के खाते वाली सीट थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन के राज्यसभा के लिये चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। जाहिर तौर पर यह सामान्य विधानसभा सीट नहीं थी, इसको फिर से हासिल करना भाजपा की प्राथमिकता भी रही होगी। कमोबेश भाजपा के लिये ऐसी ही निराशाजनक खबरें अन्य राज्यों से भी आई हैं। लंबे समय से भाजपा का गढ़ माने जाने वाले एक और राज्य मध्यप्रदेश में भाजपा उम्मीदवार को हार मिली। मध्य प्रदेश की दतिया सीट कांग्रेस ने कब्जा ली है। दरअसल, इस सीट में उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर खासा बवाल हुआ था। पिछली भाजपा सरकार में इस सीट से एक दिग्गज मंत्री बने थे। इस बार उनको टिकट न मिलने पर उग्र प्रदर्शन व धरने हुए थे। इस बड़े विवाद का फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी को हुआ। हां, भाजपा के लिए एक सुकूनभरी खबर गुजरात से आई। पार्टी के इस परंपरागत गढ़ में उपचुनाव के बाद, वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। बहरहाल, बिहार में बांकीपुर सीट को खो देना भाजपा को परेशान करने वाला जरूर है। बांकीपुर का बदला जनादेश न सिर्फ नितिन नवीन के लिये, बल्कि बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिये भी असहज करने वाली स्थिति है। दरअसल, प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने स्थानीय मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री पर तीखे हमले किये थे। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों को लगातार विभिन्न मंचों से उठाया था। जाहिर है अब मुख्यमंत्री को पार्टी के भीतर ही जवाबदेही को लेकर मुश्किल स्थिति का सामना करना होगा। वहीं इस जीत से प्रशांत किशोर के हौसले बुलंद हैं। वह देश के कई दिग्गज राजनेताओं के चुनाव अभियानों के सारथी रह चुके हैं। वे जनता के मिजाज को भांपने का हुनर भी जानते हैं। अब अपनी जीत से उत्साहित प्रशांत किशोर राज्य सरकार के खिलाफ अपना रुख और सख्त करेंगे। वे आने वाले समय में बिहार में जन सुराज पार्टी को तीसरे मोर्चे के तौर पर पेश करने की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच असहज होता गठबंधन, पहले ही प्रशांत किशोर के लिये अनुकूल स्थितियां बना रहा है। राजनीतिक पंडित इन उप-चुनावों के परिणामों की अलग-अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं। दरअसल, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव, नीट पेपर लीक और दूसरे मुद्दों को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों के बाद पहली चुनावी लड़ाई थी।

दुनिया में 60 फीसदी शिशु माँ के दूध से वंचित

(लेखक- मुकेश तिवारी)

(विश्व स्तनपान सप्ताह पर विशेष)

यूनिसेफ के आंकड़ों पर गौर करने से ही स्पष्ट हो जाता है कि , दुनिया के तकरीबन 75 करोड़ नवजात शिशु अथवा हर दो में से एक नवजात शिशु को मां का दूध पहले एक घंटे में उपलब्ध नहीं हो पता है। यही कारण है यह आंकडा शिशु मृत्यु दर के लिए बेहद अहम है। यूनिसेफ के मुताबिक 2 से 23 घंटे तक माँ का दूध नहीं मिलने से बच्चे के जन्म से 28 दिनों के भीतर मृत्यु दर का आंकड़ा 40 फीसदी होता है। जबकि जन्म के 24 घंटे बाद भी दूध न मिलने से मृत्यु दर का यही आंकडा बढकर 80 प्रतिशत तक पहुँच जाता है।

यूनिसेफ के अनुसार यदि जन्म से छह महीने तक शिशु को स्तनपान कराया जाए तो मृतक शिशुओ की संख्या 8 लाख तक कम की जा सकती है। उक्त रिसर्च पिछले 15 बषो के आधार पर तय की गई है। भारत में छोड़ जहाँ नवजात शिशुओं को माँ का दूध न मिल पाने का औसत 45 फीसदी तक है।

हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में 2016 में माँ के दूध का पहला बैंक खोला गया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के फोटिश ला फेम हॉस्पिटल ने स्वयं सेवी संस्था बेस्ट मिल्क फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अनूठी पहल की है। इस हूमन मिल्क बैंक का नाम अमारा रखा गया है। जहाँ सिर्फ 60 दिनों के भीतर 80 लीटर से ज्यादा न ब्रेस्ट मिल्क एकत्रित किया गया। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर जिले के आरएनटी मेडिकल कालेज स्थित शासकीय पन्ना धाय महिला चिकित्सालय के एक हिस्से में योग गुरु की स्वयंसेवी संस्था ने दिव्य मदर मिल्क बैंक की स्थापना की। इसी तरह दिव्य मदर मिल्क बैंक की तर्ज पर ही राज्य की राजधानी जयपुर के जे के लोन अस्पताल में चल रहे महिला चिकित्सालय में प्रदेश सरकार और नॉवे सरकार की भागीदारी से जीवनधारा नाम का मदर मिल्क बैंक खोला गया है जो राजस्थान का प्रथम सरकारी और उत्तर भारत का दूसरा मदर मिल्क बैंक है। अब तक हिन्दुस्तान भर में दो दर्जन से ज्यादा व्रेस्ट मिल्क डोनर्स सेन्टर पिछले एक साल में खुल चुके हैं।

मुम्बई के लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल अस्पताल में 1989 में स्थापित किए गए एशिया के सबसे पहले हामन मिल्क बैंक स्नेह को अब सायन मिल्क बैंक के नाम से जाना जाता है। यहाँ की निदेशिका का कहना है माँ का दूध तो शिशु का सवोतम आहार है ही लेकिन कई बार उच्च रक्तचाप ,अधिक रक्तस्राव या तेज बुखार के चलते माँ शिशु को दूध नहीं पिला पाती है। उस स्थिति में किसी दूसरी माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। लेकिन यह सीधा नवजात शिशु को नहीं दिया जा सकता है। उससे पहले कुछ सेफ्टी टेस्ट करने पडते है और सावधानियां भी बरतनी होती है। डोनर माँ का स्वस्थ होना बेहद जरुरी है। ऐसी मांओ से इलेक्ट्रॉनिक पंप की मदद से दूध निकाला जाता है। जिसे बैंक में 65.5 डिग्री सेटीग्रेड के तापमान पर 30 मिनट तक पॉश्चयुराइज करने के पश्चात 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा किया जाता है। इसके पश्चात परिक्षण होता है। सेफ्टी टेस्ट करने पडते है और सावधानियां भी बरतनी होती है। डोनर माँ का स्वस्थ होना बेहद जरुरी है। ऐसी मांओ से इलेक्ट्रॉनिक पंप की मदद से दूध निकाला जाता है। जिसे बैंक में 65.5 डिग्री सेटीग्रेड के तापमान पर 30 मिनट तक पॉश्चयुराइज करने के पश्चात 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा किया जाता है। इसके पश्चात परिक्षण होता है।

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जहाँ मृत्यु दर का वैश्विक औसत प्रति एक हजार पर 49.4 है वही हिदुस्तान का औसत 38 है। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार पर 39 और जन्म के पहले पांच साल में होने वाली मौते प्रति एक हजार पर 48 के मामले मे भी हिन्दुस्तान आगे है जो कि काफी चिंताजनक है। शिशु मृत्यु पर रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निधारित विकास लक्ष्य अभी हिन्दुस्तान की पहुंच से काफी दूर है।

मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में छह महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने का का प्रतिशत 55.8 प्रतिशत है। इसी वजह से ग्रामीण इलाकों में 42 प्रतिशत बच्चे कम वजन ,33.2 प्रतिशत ढिगने कद काठी के और 24.9 प्रतिशत दुबले होते है, चिंता की बात यह है कि छह महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या पांच साल में 17.6 प्रतिशत तक घटी जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में डायरिया 4 प्रतिशत तक बढ़ गया है. नवजात शिशुओ की मौत की एक बड़ी वजह माँ का दूध न मिलना है। वही कुपोषण के मामले में हिन्दुस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सरकारी आकड़ों के मुताबिक हिन्दुस्तान में 5 साल से कम आयु के 42.5 प्रतिशत बच्चे कुपोषित है और 69.5 प्रतिशत बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। विश्व भर में 10 अविकसित बच्चों में से चार हमारे देश के होते हैं और पांच साल से कम उम्र के तकरीबन 15 लाख बच्चे हर साल हमारे यहाँ अपनी जान गंवाते है।

विशेषज्ञों के मुताबिक इन मौतों का कारण बच्चों में संक्रमण और उनका औसत से कम वजन का पैदा होना है। ऐसे ही बच्चे बाद में कुपोषण, डायरिया, निमोनिया जैसे रोगों की गिरफत में आ जाते हैं। जिसके चलते उनकी असमय मोत हो जाती है। इस स्थिति में नवजात बच्चे के लिए माँ का दूध जीवन रक्षक साबित होता है।

(लेखक के विषय में - स्वतंत्र पत्रकार है)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

सांख्य और कर्मयोग का संबंध

भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन (सांख्य) का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है. भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है, और फिर पूर्णज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अत- मूलत- इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है, वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। दार्शनिक शोध (सांख्य) का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार है, अत- दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अन्तर नहीं है। वस्तुत- जो पदार्थ से विरक्ति व कृष्ण में आसक्ति को एक तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है।

मायावादी संन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव संन्यासी वेदान्त सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। वैष्णव संन्यासियों को भौतिक कार्य से कोई सरोकार नहीं रहता, तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किन्तु मायावादी संन्यासी, जो सांख्य तथा वेदान्त के अध्ययन व चिन्तन में लगे रहते हैं, भगवान की दिव्य भक्ति का आनन्द नहीं उठा पाते। उनका अध्ययन अत्यन्त जटिल हो जाता है, अत- वे कभी-कभी ब्रह्म चिन्तन से ऊबकर समुचित बोध बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं।

मायावादी संन्यासी कभी-कभी आत्म-साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाजसेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अत- निष्कर्ष निकला कि कृष्णभावनामृत के कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म-अब्रह्म विषयक चिन्तन में लगे संन्यासियों से श्रेष्ठ होते हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्णभावनाभावित हो जाते हैं।

विचार मंथन

देखते ही देखते क्या से क्या हो गया?

(लेखक-सनत जैन)

राजनीति में समय से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। जो सत्ता कल तक अजेय दिखाई दे रही थी, वह अचानक सवालों के घेरे में आ गई है। पिछले एक-डेढ़ महीने की घटनाओं ने भारतीय राजनीति में ऐसा माहौल पैदा किया है। जिन मुद्दों और रणनीतियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले एक दशक से अधिक समय तक अपनी राजनीतिक बढ़त बनाए रखी, आज कई मामलों में मोदी सरकार और भाजपा के लिए चुनौती बन रहे हैं। संसद का मानसून सत्र लगातार टकराव का मंच बना हुआ है। पहले पेपर लीक, फिर धार्मिक संस्थानों से जुड़ी कथित अनियमितताएं, छात्र आंदोलनों पर पुलिस कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर विपक्ष संगठित रूप से हमलावर है। विपक्ष का आरोप है, सरकार महत्वपूर्ण सवालों से बचती नजर आ रही है। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है, कि विपक्ष व्यवधान पैदा कर रहा है। इस राजनीतिक रस्साकशी ने सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया है। सत्ता की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्म विश्वास और जनविश्वास होता है। जब छोटे-छोटे मुद्दे भी बड़े जनआंदोलन का रूप लेने लगें, तब यह संकेत होता है, जनता के भीतर फैले असंतोष को प्रशासनिक उपायों तथा ताकत के बल पर नहीं रोका जा सकता है। किसी आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग, पुलिस कार्रवाई या प्रशासनिक कठोरता का सहारा लिया जाता है। उसके बाद भी विरोध लगातार फैलता जा रहा है, तो यह सरकार के लिए चेतावनी माना जाता है। हाल के उपचुनावों ने मोदी सरकार और भाजपा को राजनीतिक संदेश दिया है। चुनावी जीत और हार लोकतंत्र का सामान्य हिस्सा हैं। जब हार उन क्षेत्रों में होने लगे जिन्हें पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा हो। तब संगठन के भीतर भी आत्ममंथन शुरू हो जाता है। टिकट वितरण, स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी जैसे प्रश्न खुलकर सामने आने लगते हैं। विपक्ष इन परिणामों को सत्ता के खिलाफ जनमत का संकेत बताने में जुटा है। विपक्ष ने आपदा में अवसर खोज लिया है। चंदा चोरी और दिल्ली में पुलिस बर्बरता के बाद गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। वर्तमान परिस्थितियों में विपक्ष डू और डाई की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहा है। विपक्ष की रणनीति अब केवल संसद तक सीमित नहीं रही। सड़क से सदन तक एक साथ दबाव बनाने में विपक्ष सफल होता हुआ दिख रहा है। सरकार की ओर से सदन के नेता प्रधानमंत्री मोदी ओर वरिष्ठ नेतृत्व सदन में उपस्थित नहीं दिखाई देता है। इस कारण विपक्ष को राजनीतिक हमला तेज करने का अवसर मिल गया है। लोकतंत्र में केवल निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उन निर्णयों का प्रभावी बचाव करना और जनता के सामने पक्ष रखना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है।

राजनीति का पुराना सिद्धांत है, सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी विरोध नहीं, बल्कि आंतरिक असंतोष होता है। जब संगठन के भीतर टिकट, नेतृत्व और भविष्य को लेकर असमंजस बढ़ने लगे, तब विरोधी दलों को अतिरिक्त ताकत मिल जाती है। ऐसे समय में अनुशासन बनाए रखना और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। हालांकि यह भी उतना ही सच है, भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में कई कठिन राजनीतिक परिस्थितियों का मुकाबला किया है। इसलिए वर्तमान की घटनाओं के आधार पर अंतिम राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लोकतंत्र में जनता का अंतिम फैसला चुनावी मैदान से सामने आता है। विपक्ष के लिए यह आवश्यक है, वह विरोध तक सीमित न रहे। जनता की समस्याओं को ही आंदोलन का रूप दे। वैकल्पिक आधार पर दृष्टि और ठोस नीति भी प्रस्तुत करे। इतना स्पष्ट है, देश की राजनीति तेजी से करवट ले रही है। सत्ता पक्ष के सामने कई ऐसी चुनौतियां सामने आई हैं, जिसका निराकरण आसानी से संभव नहीं है। सत्ता पक्ष के कमजोर होने से विपक्ष को नया उत्साह और ऊर्जा मिली है। जनता की अपेक्षाएं पहले से अधिक बढ़ गई हैं। आने वाले महीनों में यह तय होगा, जेन-जी, जेन-अल्फा, विपक्षी दलों और विभिन्न आरोपों के चलते भाजपा इन चुनौतियों का मुकाबला कर पाती है या नहीं। विपक्ष इस राजनीतिक माहौल को स्थायी जनसमर्थन में परिवर्तित कर पाएगा? लोकतंत्र का यही स्वभाव है, कोई भी राजनीतिक स्थिति स्थायी और लंबे समय तक प्रभावी नहीं होती है।

समय का चक्र हर किसी की परीक्षा अवश्य लेता है। जिस तरह से एक के बाद एक चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव और 2047 तक शासन करने का जो ताना-बाना भाजपा ने बुन रखा था, वह ताना-बाना तेजी के साथ बिखर रहा है। ऐसा लगता है कि मकड़ी जो जाल दूसरों के लिए बुनती है। उसी जाल में मकड़ी फंस जाती है। उसे बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलता है। उस जाल में फंसकर वह भी समाप्त हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी संघ और मोदी सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ईरान वार्ता और हॉर्मुज स्ट्रेट की अटकलों से सोना-चांदी चमके

सोने के भाव 644 तेज होकर 1,43,600 रुपए, चांदी 1,397 चढ़कर 2,19,150 रुपए

नई दिल्ली।

वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच मंगलवार को सोना और चांदी के वायदा भाव में जोरदार तेजी दर्ज की गई। अमेरिका-ईरान वार्ता और हॉर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने की संभावनाओं पर निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है, जिसने इन कीमती धातुओं को मजबूत सहारा दिया। खबर लिखे जाने तक ग्लोबल कॉमेक्स पर सोना 4,115 डॉलर और चांदी 58.90 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही थी, जबकि घरेलू एमसीएक्स पर सोना 1,43,600 रुपये और चांदी 2,19,150 रुपये के करीब पहुंच गई। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर सोने के बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत 644 रुपये की मजबूत तेजी के साथ 1,43,559 रुपये पर हुई, जबकि पिछला बंद भाव 1,42,915 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 692 रुपये की तेजी के साथ 1,43,607 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस साल सोने ने 1,80,779 रुपये का सर्वोच्च स्तर छुआ था। वहीं चांदी के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ने भी रफ्तार पकड़ी। यह 1,397 रुपये की तेजी के साथ 2,18,143 रुपये पर खुला, जो पिछले बंद भाव 2,16,746 रुपये से काफी ऊपर था। वर्तमान में यह 2,404 रुपये की छलांग के साथ 2,19,150 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। चांदी ने इस साल 4,20,048 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर बनाया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर भी सोने और चांदी के वायदा भाव में तेज उछाल देखा गया। सोना 4,109.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 4,090.50 डॉलर प्रति औंस से अधिक था। खबर लिखे जाने तक यह 23.30 डॉलर की तेजी के साथ 4,113.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इस साल सोने ने 5,586.20 डॉलर का सर्वोच्च स्तर छुआ था। चांदी का वायदा भाव 58.38 डॉलर प्रति औंस पर खुला, जबकि पिछला क्लोजिंग प्राइस 57.85 डॉलर था। यह भी तेजी बरकरार रखते हुए 1.03 डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 58.88 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था। चांदी के भाव ने इस साल 121.79 डॉलर का उच्चतम स्तर छू लिया था।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार

मुंबई ।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शेयर बाजारों में मंगलवार को मिश्रित रुख देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 करीब 0.82 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 लगभग 1.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव पर भी वैश्विक निवेशकों की नजर बनी हुई है। सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। डॉव जोन्स में 1.32 प्रतिशत, एसएंडपी 500 में 1.48 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट में 2.13 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी बाजारों की यह मजबूती आज घरेलू बाजार के लिए कुछ सकारात्मक संकेत दे सकती है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज का मुनाफा घटकर 349 करोड़ हुआ

नई दिल्ली । रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मुनाफा 42 प्रतिशत घटकर 349.38 करोड़ रुपये रह गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 598.40 करोड़ रुपये था। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय भी घटकर 1,345.04 करोड़ रुपये रह गई जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,620.34 करोड़ रुपये थी।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 210 अंक, निफ्टी 159 अंक गिरा

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दूनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवली हावी रहने से आई है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरो वाला बीएसई सेंसेक्स 210 अंक की गिरावट के साथ ही ही 78,428.95 अंक पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,614.90 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव रहा। निफ्टी मिडकैप बाजार बंद होने तक 86 अंक की गिरावट के साथ ही 18,215.85 अंक पर बंद हुआ।सबसे अधिक लाभ वाले शेयरों में आज सीजी पावर , और सेल रहे । वहीं गॉडफ्रे फिलिप और निप्पन के शेयरों में भी अच्छी तेजी रही। एलआईसी इंडिया, यूपीएल, प्रेस्टीज एस्टेट और डाबर इंडिया गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की मिश्रित शुरुआत रही। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 147 अंक बढ़कर 78,786.10 पर था, जबकि निफ्टी 162 अंक गिरकर 24,611.55 पर कारोबार कर रहा था।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को भारतीय रुपया 19 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.19 पर बंद हुआ। आज सुबह शुरुआती कारोबार में सपाट खुला और तीन पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.34 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि कच्चे तेल की अपेक्षाकृत कम कीमतों और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से आयातकों की डॉलर की मांग पर असर पड़ा। अब बाजार की नजर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसले और इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिका के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.35 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में 95.34 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव की तुलना में तीन पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.37 पर बंद हुआ था।

भारत ने 5 उत्पादों पर बढ़ाए डंपिंग रोधी शुल्क

चार मौजूदा उत्पादों पर शुल्क अवधि बढ़ी, एक नए उत्पाद पर भी लगा शुल्क

नई दिल्ली ।

घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिशों पर चार मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्कों की अवधि बढ़ाई है और एक नए उत्पाद पर भी पांच साल के लिए शुल्क लगाया है। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से आयातित 'लो ऐश मेटलर्जिकल कोक' पर पांच वर्षों के लिए 42.95 डॉलर से 128.83 डॉलर प्रति टन के बीच नया डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है।

जिन उत्पादों पर शुल्क की अवधि बढ़ाई गई है, उनमें अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका, एरिलाइड्स, लौह/इस्पात से बने सीमलेस ट्यूब, पाइप व खोखले प्रोफाइल तथा नॉर्मल ब्यूटेनॉल शामिल हैं। पेंट, सौंदर्य प्रसाधन, औषधि और प्रिंटिंग इंक जैसे उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले इन उत्पादों का चीन, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से लगातार सस्ता आयात हो रहा था, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहे थे।

अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका पर यह शुल्क फरवरी 2027 तक, एरिलाइड्स पर जनवरी 2024 तक और लौह व इस्पात उत्पादों पर जनवरी 2027 तक बढ़ाया गया है। नॉर्मल ब्यूटेनॉल पर भी पांच वर्षों के लिए अवधि बढ़ाई गई है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बहुपक्षीय ढांचे के तहत ये शुल्क निष्पक्ष व्यापार और घरेलू उत्पादकों को समान प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं।

अब 25,000 तक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी भी पीएफ के दायरे में

पीएफ की वेज सीलिंग लिमिट 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए हुई

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने प्रोविडेंड फंड (पीएफ) से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। पीएफ की वेज सीलिंग लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जिसका सीधा असर लाखों नौकरीपेशा लोगों की मासिक सैलरी और रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। इस बदलाव से अब ज्यादा कर्मचारी पीएफ और पेंशन योजना (ईपीएस) के दायरे में आ सकेंगे, हालांकि शुरुआत में हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत होगी। पहले नियम के अनुसार, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 15,000 रुपये तक होता था, उनके लिए पीएफ कटवाना अनिवार्य था। 15,000 रुपये से अधिक आय वाले कर्मचारी इससे बाहर रह सकते थे। नई लिमिट 25,000 रुपये होने के बाद अब 15,001 रुपये से 25,000 रुपये तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी पीएफ के दायरे में आ जाएंगे, जिससे उन्हें बचत के साथ-साथ पेंशन का लाभ भी मिलेगा। इस बदलाव से पीएफ में ज्यादा योगदान जाने के कारण हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी में कुछ कमी देखी जा सकती है। दरअसल, कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है और कंपनी भी अपनी ओर से इतना ही योगदान देती है। उदाहरण के लिए, 22,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को अब 2,640 रुपये पीएफ के रूप में कटवाने होंगे, जबकि पहले वह दायरे में नहीं था। इसी तरह, 25,000 रुपये बेसिक सैलरी पर पीएफ योगदान 1,800 रुपये (15,000 पर) से बढ़कर 3,000 रुपये (25,000 पर) हो जाएगा। यह बदलाव कई कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा को बढ़ाने वाला साबित होगा, खासकर उनके लिए जो पहले इस सीमा के कारण पीएफ और पेंशन योजना से नहीं जुड़ पा रहे थे। हालांकि, कंपनियों और सरकार पर भी इससे अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन यह कदम कर्मचारियों की लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा।

वैश्विक दबाव में बढ़ी थोक महंगाई, सरकार बोली- खुदरा नियंत्रण में जून में

डब्ल्यूपीआई 9.87 फीसदी हुई, वित्त राज्य मंत्री ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को बताया मुख्य कारण

नई दिल्ली।

सरकार ने संसद को बताया है कि जून में थोक महंगाई (डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन) में बढ़ोतरी का मुख्य कारण वैश्विक बाजार में ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें रही हैं। हालांकि, सरकार का दावा है कि उसने आम लोगों को प्रभावित करने वाली खुदरा महंगाई (सीपीआई) को काफी हद तक नियंत्रण में रखने में सफलता पाई है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि खनिज तेल, खाद्य पदार्थ, धातु, रसायन और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वैश्विक तेजी का असर थोक महंगाई पर दिखा है। सरकार महंगाई को नियंत्रित करने और आम लोगों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। इन उपायों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बढ़ाना, खुले बाजार में अनाज की बिक्री करना और जरूरत के अनुसार व्यापार नीतियों में बदलाव करना शामिल है। इनका उद्देश्य खाद्य कीमतों को नियंत्रित कर उपभोक्ताओं को राहत देना है। आंकड़ों के अनुसार, जून में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 9.87 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो मई में 9.68 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, खुदरा महंगाई दर सरकार द्वारा तय लक्ष्य के दायरे में बनी हुई है।

हालांकि, जून 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38 प्रतिशत पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में वृद्धि को माना जा रहा है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक के लिए खुदरा महंगाई का लक्ष्य 4 प्रतिशत तय किया है।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का मुनाफा 3 फीसदी बढ़कर 873 करोड़ पहुंचा

नई दिल्ली

। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने बताया कि जून, 2026 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका मुनाफा सालाना आधार पर तीन प्रतिशत बढ़कर 873 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 845 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने शेयर बाजार को बताया कि जून तिमाही में उसकी कुल आय पांच प्रतिशत बढ़कर 1,385 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1,324.8 करोड़ रुपए थी। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च आठ प्रतिशत बढ़कर 242 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 224 करोड़ रुपए था। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने समीक्षाधीन तिमाही के दौरान 15.1 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड प्रबंधक के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा।

भारत के निजी विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि जुलाई में 5 साल के निचले स्तर पर

एचएसबीसी पीएमआई जून के 54.2 से गिरकर 53.5 हुआ

नई दिल्ली ।

भारत के निजी क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियों की वृद्धि जुलाई माह में पांच वर्षों में सबसे सुस्त गति से हुई है। एक निजी सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। एचएसबीसी का भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई), जो विनिर्माण गतिविधियों में बदलाव पर नज़र रखता है, जून के 54.2 से गिरकर जुलाई में 53.5 पर पहुंच गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कुल बिक्री में गिरावट और नए ऑर्डर व नौकरी सृजन में कमी को इस सुस्ती का मुख्य कारण बताया गया है। जुलाई का 53.5 का आंकड़ा अगस्त 2021 के बाद सबसे कम है, जब यह 52.3 था।

हालांकि, यह सूचकांक 50 के स्तर से ऊपर बना हुआ है, जो गतिविधियों में विस्तार का संकेत देता है। यह लगातार 57वां महीना है जब विनिर्माण गतिविधियों में विस्तार देखा गया है। एचएसबीसी की एक चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट ने बताया कि जुलाई में आपूर्तिकर्ता की आपूर्ति के समय का सूचकांक बढ़ा है, जो आपूर्ति श्रृंखला में सुधार का संकेत है। हालांकि, मध्य पूर्व में फिर से बढ़े तनाव ने इन सुधारों के स्थायित्व पर नए संदेह पैदा कर दिए हैं। इसके चलते विनिर्माता बफर बना रहे हैं, जिससे इनपुट और तैयार माल दोनों की इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार नए ऑर्डर में वृद्धि चार साल से अधिक समय में दूसरी सबसे कमजोर रही, जिसका मुख्य कारण बाजार की मुश्किल होती स्थितियां और ग्राहकों की कम दिलचस्पी बताई गई है।

बिक्री के मामले में भी वृद्धि की गति 2022 के मध्य के बाद से सबसे धीमी थी। जुलाई में उपभोक्ता सामान क्षेत्र सबसे कमजोर रहा, जिसमें नए ऑर्डर और आउटपुट में काफी कम वृद्धि देखी गई, जबकि इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियों ने दोनों पैमानों पर मजबूत विस्तार दर्ज किया। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त इनपुट की खरीद 31 महीने के निचले स्तर पर आ गई। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ने की रफ्तार लगातार तीसरे महीने धीमी रही और यह लगातार 29 महीनों की वृद्धि में सबसे धीमी दर थी।

हालांकि, लागत का दबाव पांच महीनों में सबसे कम स्तर पर आ गया, लेकिन कंपनियों ने विशेषकर सामान की आवाजाही के लिए ज्यादा कीमतें बताईं।

यूपीआई नियमों में होगा बदलाव, भविष्य में लग सकता है एमडीआर

वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली ।

वित्त मंत्रालय ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे भविष्य में यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने का अधिकार मिल सकेगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ग्राहकों के लिए कोई नया शुल्क लागू नहीं किया गया है और इसका उद्देश्य यूपीआई यूजर्स से अतिरिक्त चार्ज वसूलना नहीं है। यदि भविष्य में एमडीआर लागू भी होता है, तो इसका असर मुख्य रूप से कारोबारियों (मर्चेंट्स) पर पड़ सकता है। यह प्रस्ताव पेमेंट एक्ट की धारा 10ए को हटाने के लिए है, जो वर्तमान में डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लगाने से रोकती है। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के अनुसार, देश के 88 फीसदी डिजिटल भुगतान यूपीआई से होते हैं और अरबों ट्रांजैक्शन की बढ़ती लागत ने बैंकों व पेमेंट कंपनियों पर दबाव बढ़ाया है। डिजिटल पेमेंट उद्योग लंबे समय से जीरो एमडीआर नीति की समीक्षा की मांग कर रहा है, क्योंकि प्रोत्साहन राशि वास्तविक लागत से कम है। कुछ संगठनों ने बड़े कारोबारियों पर सीमित एमडीआर और छोटे को छूट देने का सुझाव दिया है।

एलआईसी में सरकार बेचेगी 6.5 फीसदी हिस्सेदारी

आम निवेशकों को मिलेगा शेयर खरीदने का मौका

मुंबई ।

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है।

केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए बेचने का फैसला किया है। पहले चरण में 2.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची जाएगी, जिसे ग्रीन शू ऑप्शन के तहत कुल 6.5 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का यह कदम सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग नियमों के अनुपालन हेतु उठाया जा रहा है। सरकार ने इस ऑफर फॉर सेल के लिए 382 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस निर्धारित किया है, जिसका अर्थ है कि इससे कम कीमत पर शेयर नहीं खरीदे जा सकेंगे। वर्तमान में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की करीब 96.5 फीसदी हिस्सेदारी है। इस पेशकश में पहले गैर-खुदरा निवेशकों (संस्थागत निवेशक) को हिस्सा खरीदने का मौका मिलेगा, जिसके बाद खुदरा निवेशक भी अगले दिन अपनी बोली लगा सकेंगे।

पहले चरण में 2.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची जाएगी, लेकिन निवेशकों की अच्छी मांग पर ग्रीन शू ऑप्शन के तहत 4 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है, यानी कुल 6.5 फीसदी तक शेयर बाजार में आ सकते हैं। सरकार का यह निर्णय केवल पूंजी जुटाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक नियामक उद्देश्य के लिए भी है। सेबी के नियमों के अनुसार शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी हिस्सेदारी आम निवेशकों (पब्लिक) के पास होनी चाहिए। एलआईसी जिसकी लिस्टिंग साल 2022 में हुई थी और जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ था, अब इस ओएफएस के माध्यम से अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाएगी। इस कदम से कंपनी में शेयरों की तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ेगी और वह नियामक मानकों के अधिक करीब पहुंचेगी।

मस्क की बादशाहत बरकरार, अमेरिकी टेक दिग्गजों का दबदबा

मस्क नंबर 1; टॉप-9 में अमेरिकी टेक महारथी, अर्नाल्ट की बादशाहत पर खतरा

नई दिल्ली ।

वैश्विक अरबपतियों की सूची में एलन मस्क ने अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी है, बावजूद इसके कि उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष दस में से नौ स्थान अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गजों ने कब्जा रखे हैं, जो इस क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर पहले पायदान पर बने हुए हैं। उनका कुल नेटवर्थ 684 अरब डॉलर है, जो दूसरे नंबर के लैरी पेज (305 अरब डॉलर) से दोगुने से भी अधिक है। गौरतलब है कि मस्क ने 400 अरब डॉलर गंवाने के बावजूद यह स्थान बनाए रखा है। जेफ बेजोस 290 अरब डॉलर के साथ तीसरे और सर्गी ब्रिन 283 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर हैं। बेजोस की संपत्ति में 32.3 अरब डॉलर और ब्रिन की संपत्ति में 16.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इसके बाद माइकल डेल (217 अरब डॉलर) पांचवें, मार्क जुकरबर्ग (199 अरब डॉलर) छठे, लैरी एलिसन (181 अरब डॉलर) सातवें, जेनसेन हुआंग (166 अरब डॉलर) आठवें और स्टीव बाल्मर (163 अरब डॉलर) नौवें स्थान पर हैं। इन शीर्ष नौ नामों में अमेरिकी टेक दिग्गजों का दबदबा स्पष्ट है। अब सवाल यह है कि क्या लंबे समय से टॉप-10 में अपनी जगह बनाए रखने वाले एकमात्र गैर-अमेरिकी, बर्नार्ड अर्नाल्ट इस सूची से बाहर हो जाएंगे? 11वें नंबर पर काबिज वॉरेन बफे (145 अरब डॉलर) से अर्नाल्ट का फासला केवल 16 अरब डॉलर का है। चूंकि अरबपतियों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी कंपनियों के शेयरों से आता है, ऐसे में शेयर बाजार में जरा सा भी उतार-चढ़ाव इस सूची में बड़ा फेरबदल कर सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जॉब के लिए इन चीजों की कुर्बानी कभी न दें

हम आठ से दस घंटे जॉब करते हैं और वह भी अपना पूरा सौ प्रतिशत देकर। आप भले ही अपने जॉब से कितना भी प्यार क्यों न करते हों लेकिन आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सीमा बनाकर रखने की जरूरत होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा काम, हमारा स्वास्थ्य, हमारा निजी जिंदगी प्रभावित होगी। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे आपको अपने जॉब के लिए कभी कुर्बान नहीं करना चाहिए।

आपका स्वास्थ्य

यह बहुत ही मुश्किल होता है कि काम के समय आप अपने स्वास्थ्य के लिए सीमा तैयार कर ले क्योंकि आपको इसके दुष्प्रभाव का अंदाज ही नहीं होता। आप तनाव का स्वागत करते हैं, नींद खो देते हैं और बिना व्यायाम के लंबे समय पर बैठकर काम करते हैं। जब तब आपको इस बारे में पता चलेगा आपकी हालत खराब हो चुकी होगी। इसलिए इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपकी जॉब के कारण आपके हेल्थ पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जिसकी कीमत आपके स्वास्थ्य से बढ़कर हो।

आपका परिवार

यह बहुत ही आसान होता है कि आपका परिवार आपके जॉब के कारण प्रभावित हो रहा हो। हममें से कई लोग यह करते हैं क्योंकि हम हमारी नौकरी को हमारे परिवार का चलाने का साधन मानते हैं। आप यह सोचते हैं कि बच्चों को अच्छे कॉलेज-स्कूल में पढ़ाना है तो मुझे ज्यादा पैसा कमाना होगा। बस फिर क्या आप परिवार के साथ क्वॉलिटी टाइम भी नहीं बिता पाते। आप ऐसी कई मेमोरिज मिस कर देते हैं जो आपके परिवार को खुशियां देती है।

आपका विवेक

वह जॉब जो आपके विवेक का एक छोटा सा हिस्सा भी ले ले तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। आपका विवेक कुछ ऐसा है कि इसे आपको ही मॉनिटर करना होगा और खुद को हेल्दी रखने के लिए सीमाएं तय करनी होगी।

आपकी पहचान

जब आपका काम आपकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है तो यह खतरनाक साबित हो सकता है कि आपकी पूरी पहचान केवल आपका काम ही हो। अपनी पहचान के बाहर का काम कर के आपको सुखद एहसास होगा। यह आपके तनाव दूर करने में मदद करेगा और एक व्यक्ति के रूप में विकास करने में मददगार साबित होगा।

आपके संपर्क

आपके संपर्क आपकी मेहनत और प्रयास का उत्पाद है। किसी भी जॉब की खातिर आप अपने अच्छे संपर्क सूत्रों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं।

इस तरह बना सकते हैं ग्रह, नक्षत्रों में करियर

इन दिनों युवाओं में ज्योतिष की पढ़ाई को लेकर भी खूब क्रेज है। बाजार में ज्योतिषियों की बढ़ती मांग को देखते हुए युवाओं को इसमें भविष्य संवारने का सुनहरा मौका दिया है। ज्योतिष कोर्स को लेकर युवाओं के बढ़ते रुझान को देखते हुए यह एक बेहतरीन करियर विकल्प बन गया है। पिछले कुछ सालों में इस फील्ड में काफी स्कोप बढ़ा है। यही नहीं ज्योतिष के साथ पूजा-पाठ में करियर का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है। जहां लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, वहीं ग्रह-नक्षत्र को शांत करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं।

कुंडली मिलान से लेकर, मांगलिक कार्य, शादी ब्याह, पंचाग, राशिफल, अंकविज्ञान, कर्मकांड आदि भी इसी दायरे में आते हैं। ज्योतिष, पूजा-पाठ के कई तरह के कोर्स उपलब्ध है। 12 वीं करने के बाद भी आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। स्नातक ऑनर्स या शास्त्री की डिग्री तीन साल की होती है। दो साल का पीजी कोर्स या आचार्य की डिग्री हासिल की जा सकती है। आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ज्योतिष अलंकार कोर्स के लिए 12वीं पास होना जरूरी है।

इसके बाद आप ज्योतिषाचार्य का कोर्स कर सकते हैं। ज्योतिष और अध्यात्म के साथ-साथ पूजा-पाठ में करियर का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है। जहां लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, वहीं ग्रह-नक्षत्र को शांत करने के लिए भी धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं। अधिकतर संस्थानों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत के साथ ही ज्योतिष विज्ञान, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, व्याकरण, वेद, पुरोहित आदि की पढ़ाई होती है। वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वैदिक दर्शन, जैन-बुध्द दर्शन, धर्मशास्त्र मीमांसा, धर्मागम आदि का अध्ययन संस्कृत विषय के तहत ही किया जाता है। हालांकि कई संस्थानों में ज्योतिष प्रज्ञ में सर्टिफिकेट कोर्स तो ज्योतिष भूषण में डिप्लोमा कोर्स भी आयोजित कर रहे हैं।

संभावनाएं

ज्योतिष में करियर बनाने के इच्छुक लोगों को रत्न, पत्थर, ग्रह-नक्षत्र के साथ भारतीय लोगों के दृष्टिकोण को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में कभी भी मंदी नहीं आती क्योंकि अधिकतर भारतीय पारंपरिक हैं और ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति अखबार, न्यूज चैनलों के अलावा पत्रिकाओं में भविष्यवक्ता भी बन सकता है।

स्किल्स

इस फील्ड में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप में लगातार कुछ न कुछ सीखने के गुण हों। आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो, आप लोगों के साथ दोस्ताना रवैया रख सकें। केवल पैसा कमाना ही आपका मकसद न होकर दूसरों की सहायता करना भी होना चाहिए। ईमानदारी इस पेशे में काफी अहमियत रखती है। साथ ही, जिम्मेदारी की भावना भी आप में कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए। लोगों को अपनी बातों से कंविंस करना इस फील्ड की मुख्य चुनौती है। आप अपनी बात हर समय तर्कयुक्त ढंग से रखें जिससे सामने वाला आपकी बातों पर हामी भरे। ज्योतिष सीखना और भविष्यवाणी करना आसान काम नहीं है। इसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है।

कोर्सेस

बीएससी इन एस्ट्रोलॉजी, एमएससी इन एस्ट्रोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी, डिप्लोमा कोर्स इन भारतीय ज्योतिष, बीएम/एमए/पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, एमए इन संस्कृत रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी, कोर्स इन वेदांग ज्योतिष, टू ईयर ग्रेडेट कोर्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एम इन एस्ट्रोलॉजी (पत्राचार), बीए (संस्कृत), ज्योतिष एमए (आचार्य), ज्योतिष बीए (संस्कृत), ज्योतिष फलित, ज्योतिष बीए (ज्योतिष), एमए (फलित ज्योतिष), एमए (सिध्दांत ज्योतिष), बीए शास्त्री (सिध्दांत ज्योतिष), बीए (फलित ज्योतिष), ज्योतिष डिप्लोमा कोर्स, ज्योतिष डिप्लोमा पुरोहित सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स इन पुरोहित, पीजी डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र रिफ्रेशर कोर्स इन ज्योतिष (ज्योतिष प्रज्ञ और ज्योतिष भूषण), ज्योतिष प्रवीण बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स (एक साल)।

युवाओं में सिविल सर्विसेज की प्रिलिम्स, यानी सीसैट (सिविल सर्विसेज एप्टिट्यूड टेस्ट) बहुत मायने रखती है। अगर आपमें पैशन है, तो आप इस परीक्षा में अपनी योग्यता दिखाकर अच्छे अंक पा सकते हैं। जानते हैं सी-सैट सहित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित कुछ सामान्य सवालों के जवाब।

सीसैट की तैयारी में कितना समय लगता है

सीसैट (प्रिलिम्स) में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। अगर उम्मीदवार प्रिलिम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसे दोनों यानी जनरल स्टडीज पेपर 1 और जीएस मेन्स की तैयारी साथ में ही करनी चाहिए। जहां तक समय का सवाल है, तो प्रिलिम्स की तैयारी के लिए 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। अगर उम्मीदवार सही तरीके से तैयारी करे, तो वह जीएस मेन्स का 60 से 70 प्रतिशत भाग कवर कर सकता है। इसके अलावा नोट्स बनाने भी बहुत जरूरी हैं। आपको सिलेक्शन पाने के लिए कुछ हटकर करना पड़ेगा।

सीसैट व मेन्स का जीएस पेपर क्या एक-दूसरे से किसी तरह संबंधित हैं?

शायद ही इन दोनों में कुछ कॉमन हो। फिर भी, अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो एक संबंध देख सकते हैं कि अगर किसी उम्मीदवार की जीएस बहुत अच्छी है, तो यह उसे रीडिंग काम्प्रिहेंशन सेक्शन में मदद कर सकती है, जिससे सीसैट में कम से कम 40 से 60 प्रतिशत प्रश्न पूछे जाते हैं।

सीसैट पेपर 1 और 2 के लिए विद्यार्थियों की रणनीति

पेपर 1 - इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि उम्मीदवार एनसीईआरटी की पुस्तकों को बहुत अच्छे-से पढ़े। कक्षा 6 से 12 तक की हिस्ट्री, सिविक्स और जिओग्रॉफी को अच्छे से पढ़ें। कक्षा 9 से 12 तक की इकोनॉमिक्स का गहराई से अध्ययन करें और कक्षा 11 व 12 की सोशलॉजी पर फोकस करें। एनसीईआरटी बुक्स के साथ-साथ आपको एक अच्छा अखबार भी नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा वार्षिक बुक भी अच्छे से पढ़ें। आपको इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल साप्ताहिक मैगजीन भी पढ़नी चाहिए।
पेपर 2 - इसके लिए आपको कक्षा 7 से 10 तक की मैथ्स पर बहुत अच्छा

भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में MBA-MCA छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का शुभारंभ

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत। भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट (BMCM) में सोमवार को नए प्रवेशित MBA और MCA विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम-2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एवं iVIPANAN Digital Marketing Services के संस्थापक भौतिक सेठ रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को डिजिटल युग में कौशल विकास, नवाचार और करियर निर्माण के महत्व पर प्रेरक संबोधन दिया।

इस अवसर पर BMU के एकेडमिक डीन डॉ. संजय बुच ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता और प्रोफेशनल विकास के लिए प्रेरित किया। वहीं, BMCM की डायरेक्टर डॉ. श्वेता कुमार ने नवप्रवेशित छात्रों का स्वागत करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

पांच दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान साइबर सिक्योरिटी, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, उद्यमिता विकास, करियर प्लानिंग और व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत कर सकें।

इन तरीकों से दूर कर सकते हैं अपनी कमजोरियां

कई बार हम बिना सोचे-समझे दूसरों की आलोचना कर देते हैं लेकिन ऐसा करते हुए हम यह नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। दूसरों की आलोचना पर ध्यान देने या उनकी कमियां निकालने में समय गंवाने के बजाय हमें खुद को सशक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप को कमजोर या हीन समझने के बजाय यह देखें कि आखिर वह कौन-सी खासियत है, जो आपके भीतर है, जिसे आगे बढ़ाकर आप कामयाबी के शिखर की तरफ बढ़ सकते हैं। कभी भी यह न सोचें कि आपके भीतर कोई हुनर नहीं है।

अगर आपको लगता है कि वाकई कोई अच्छाई आपमें नहीं है, तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जरा ठहरें। कुछ दिन पूरी एकाग्रता के साथ आत्म-मंथन करें। अपनी रुचियों, आदतों, व्यवहार, बातचीत, प्रतिक्रिया आदि पर ध्यान दें। आपको जरूर पता चल जाएगा कि आप में कौन-सी अच्छाई है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, तो घर के किसी समझदार सदस्य, अध्यापक या फिर काउंसलर की मदद से खुद की ताकत को जानें-समझें। इससे आपको अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

घबराएं न हार से

अगर आप कभी किसी परीक्षा या टेस्ट में फेल हो जाते हैं, किसी टीम का हिस्सा होते हुए भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर किसी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी धैर्य बनाए रखें। हताश बिल्कुल न हों। खुद को संयत रखें। फिर यह सोचें कि आखिर आप असफल क्यों हुए? आपसे कहां चूक हो गई? आपने गलती कहां की? अपनी हार या असफलता में छिपे कारणों को ढूंढें। जब तक आप उन कारणों को ढूंढकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, कामयाबी आपसे दूर ही रहेगी। अगर आप खुद को विजेता के रूप में देखता चाहते हैं, तो अपनी कमियों-कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें यथाशीघ्र दूर करें। याद रखें, दुनिया में ऐसे बहुत कम कामयाब लोग होंगे, जिन्होंने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा होगा। कामयाबी के शिखर पर पहुंच चुके तमाम लोगों को अपने प्रयासों में कई बार हार मिली। चाहे बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन हों या फिर नए संसार की खोज में निकले कोलंबस और वास्को-डि-गामा जैसे लोग। बार-बार की असफलता के बावजूद ऐसे उत्साही लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया, जब उन्हें कामयाबी मिली और दुनिया भर ने उनका लोहा माना। अगर आप भी किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में असफल हो जाते हैं, तो इसे जिंदगी का आखिरी इम्तेहान समझने के बजाय इस बात पर विचार करें कि आखिर किन कमियों के कारण आपको सफलता नहीं मिल सकी। इन कमियों को दूर कर फिर दोगुने उत्साह के साथ प्रयास करें।

आत्ममुग्धता से बचें

अक्सर यह भी देखने में आता है कि छोटी-छोटी सफलताएं पाकर हम आत्ममुग्ध हो जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए किए जाने वाले हमारे प्रयास शिथिल पड़ने लगते हैं। कई बार हम खुद को बेहद काबिल मानकर यह सोच लेते हैं कि हमें सफलता तो मिल ही जाएगी। मगर जब ऐसा नहीं होता और असफलता हाथ लगती है, तो हमें शॉक लगता है। तब हमें एहसास होता है कि काश दूसरों की तारीफों के कारण हम आत्ममुग्धता के शिकार न हुए होते।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

एआई बच्चों की कर रहा निगरानी, स्टार्टअप्स ला रहे स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम

न्यूयॉर्क , एजेंसी। बच्चों की देखभाल के लिए इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट बेबी मॉनिटर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार किए जा रहे हैं। नैनिट, बेबीटेक समेत कई स्टार्टअप ऐसे सिस्टम विकसित कर रहे हैं, जो रात के दौरान बच्चे की नींद, सांस, करवट और गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं। कंपनियां भविष्य में एआई के जरिए बच्चों की दिनभर की गतिविधियों, विकास और व्यवहार का भी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में काम कर रही हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे बेबी सर्विलांस का नया दौर मान रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दीवार पर लगा सफेद कैमरा बच्चों पर सीधा नजर रखता है। एचडी वीडियो ऐसे सर्वर पर भेजी जाती है, जहां मशीन-लर्निंग एल्गोरिद्म उसके हर हिलने-डुलने और उसकी आंखें खुलने-बंद होने के सटीक समय का रिकॉर्ड रखते हैं। इन आंकड़ों को चार्ट और विश्लेषण के रूप में तैयार करते हैं। इसमें सांस लेने से लेकर सोने में लगा समय, रात के माता-पिता की जरूरत कितनी बार पड़ी, ऐसी जानकारी रिकॉर्ड की जाती हैं। नैनिट का दावा है कि उसके 10 लाख सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और सालाना आय 10 करोड़ डॉलर से अधिक है। उसका सबसे महंगा किट 474 डॉलर (करीब 45 हजार रुपये) का है। नैनिट ने निवेशकों से हाल में 5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं।

ग्रीस में आग बुझाने गए 2 हेलिकॉप्टर हवा में टकराए; 2-2 लोग सवार थे

एथेंस , एजेंसी। ग्रीस की राजधानी एथेंस के पास जंगल की आग बुझाने के दौरान रविवार को 2 फायरफाइटिंग हेलिकॉप्टर हवा में टकरा गए। हादसा पोर्टो जर्मेनो इलाके में हुआ। टक्कर के बाद एक हेलिकॉप्टर जमीन पर गिर गया। फायर विभाग के मुताबिक, दोनों हेलिकॉप्टरों में 2-2 लोग सवार थे। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक उनके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ग्रीस में तेज हवाओं के कारण जंगल की आग तेजी से फैल रही है। एथेंस के आसपास कई इलाकों में आग पहुंचने के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तेज हवा के चलते हेलिकॉप्टरों को समुद्र से पानी भरने में भी दिक्कत आ रही है।

अमेरिका में 80 वर्षीय अभिनेता विंसेंट पास्टर का शव बरामद

वाशिंगटन, एजेंसी। द सोप्रानोस में सल्वाटोर बोनपेन्सिएरो की भूमिका के लिए प्रसिद्ध अभिनेता विंसेंट पास्टर का निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। उनके मैनेजर बॉब मैकगोवन ने बताया कि पास्टर न्यूयॉर्क के सिटी आइलैंड स्थित अपने घर में मृत पाए गए। पास्टर ने 1980 के दशक से फिल्मों में अभिनय शुरू किया था। उन्होंने 1990 की गुडफेलस और अवेकनिंग्स जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना में सेवा देने वाले पास्टर अपने दयालु और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार में उनकी बेटी रेनी पास्टर हैं।

यूएई में इस साल पहली बार 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान

अबू धाबी , एजेंसी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में इस साल पहली बार तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय मौसम केंद्र (एनसीएम) के अनुसार, रविवार को देश के एक आंतरिक क्षेत्र में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। यह इस वर्ष का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गर्मियों का चरम दौर अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अगस्त के दौरान तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो सकती है, लेकिन तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस का असर कई सप्ताह तक बना रहेगा। यूएई में आमतौर पर अक्तूबर के मध्य से मौसम में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलता है। तब तक दिन के समय अत्यधिक गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाती रहेगी। भारतीय मानसून का लो-प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत और पाकिस्तान से पश्चिम की ओर बढ़कर अरब प्रायद्वीप तक पहुंच रहा है, जिससे गर्म हवा का प्रवाह तेज हो गया है। अरब प्रायद्वीप पर बने थर्मल लो प्रेशर तापमान लगातार बढ़ा रहा है। रुब-अल-खाली रेगिस्तान से आने वाली अत्यधिक गर्म हवाएं तापमान को और ऊपर ले जा रही हैं।

पाकिस्तान में पुलिस को निशाना बनाकर बड़ा फिदायीन हमला, पांच सुरक्षाकर्मियों समेत 15 की गई जान

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान का उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर भीषण आतंकी हमले से दहल उठा है। रविवार, 2 अगस्त को स्वात जिले के काबल टाउन में आयोजित एक शांति मार्च के दौरान संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 12 अन्य लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।

पुलिस स्टेशन के पास हुआ धमाका : यह विस्फोट उस समय हुआ जब स्थानीय लोगों और स्वात अमन जिरगा नामक स्थानीय परिषद द्वारा आयोजित अमन पासून शांति रैली निकाली जा रही थी। पिछले कुछ समय से इलाके में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते उग्रवाद के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शनकारी शांति की अपील के साथ हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर मार्च निकाल रहे थे, तभी काबल पुलिस स्टेशन के पास यह धमाका हुआ।

सुरक्षाबलों और नागरिकों को बनाया निशाना : क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी मलकंद द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस भीषण हमले में 5 पुलिसकर्मियों और 10 आम नागरिकों की जान चली गई है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका धुएं और चीख-पुकार से भर गया। शुरुआती जांच में यह एक फिदायीन यानी आत्मघाती हमला प्रतीत हो रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य वहां तैनात पुलिसबल और सुरक्षा घेरा था।

अस्पतालों में हाई अलर्ट : धमाके की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल 12 लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है।

जनता का फुटा गुस्सा : स्वात घाटी में पिछले कुछ महीनों से हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे स्थानीय लोग पहले से ही डरे हुए थे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन शांति की मांग कर रहे निहत्थे नागरिकों पर हुए इस हमले ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लोग आतंकवाद के खिलाफ रैली निकाल रहे थे : धमाके से पहले रविवार को कई लोग आतंकवाद के खिलाफ शांति रैली निकाल जा रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्वात में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं की निंदा की। डॉन के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके आंदोलन का एक ही मकसद है, इलाके में शांति लौटाना और आतंकवाद का खात्मा करना। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है। अगर असुरक्षा का माहौल जारी रहा तो लोगों में बड़ा जनआक्रोश पैदा हो सकता है। प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करता है, जबकि स्वात के पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी खुलेआम सक्रिय हैं।

पाक राष्ट्रपति जरदारी ने जांच के आदेश दिए : पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमाके में लोगों की मौत पर दुख जताया। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने धमाके की निंदा की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट की मांग की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, शांति के दुश्मनों को उनके नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।

वहीं, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी धमाके की निंदा करते हुए मृतकों के प्रति शोक जताया। उन्होंने कहा, 'आतंकी कायराना हमलों से देश का मनोबल नहीं तोड़ सकते।'

जुलाई में आतंकी हमलों में 154 मौतें हुई : पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की मासिक सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई है। रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में कई जिलों में आतंकवाद से जुड़ी 154 मौतें दर्ज की गईं, जबकि जून में यह संख्या 75 थी। यानी एक महीने में 105 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

ट्रंप के हमले कैंसिल करने के बाद ईरानी मीडिया ने किया ट्रोल, कहा- 'फूल की हवा निकल गई'

तेहरान, एजेंसी। ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री हमलों पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की घोषणा के बाद ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना और मजाक उड़ाया. ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में दावा किया कि यह फैसला रीजनल एक्टर्स की रिक्वेस्ट के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है, ईरान और दूसरे मिडिल ईस्टर्न देशों ने हमसे अभी-अभी कहा है कि हम कोई भी हमला न करें क्योंकि डील के पैरामीटर्स पर सहमति हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत, पूरी तरह से और पूरी तरह से खोलना शामिल होगा.' हालांकि, ईरान की सरकारी मीडिया ने मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की किसी रिक्वेस्ट की पुष्टि करने वाली या होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तेहरान के रुख में किसी बदलाव का संकेत देने वाली कोई रिपोर्ट नहीं दी. इसके बजाय ईरानी न्यूज एजेंसियों ने इस डेवलपमेंट को वॉशिंगटन की वापसी के तौर पर दिखाया. सेमी-ऑफिशियल न्यूज एजेंसी फार्स ने इस डेवलपमेंट पर रिपोर्ट करते हुए पोस्ट किया, 'ट्रंप द फूल का दम निकल गया है!' इसके साथ ही सेमी-ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर ने इस बात को खारिज कर दिया कि तेहरान ने हमले रोकने की मांग की थी, और बताया कि ट्रंप एक बार फिर अपनी खोखली धमकियों से पीछे हट गए और दुनिया के सामने अपने पीछे हटने को एक एहसान के तौर पर पेश किया. मिलिट्री अधिकारियों का हवाला देते हुए मेहर ने ट्रंप के बयान को एक नया झूठ बताया और कहा कि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी हालात के लिए तैयार है. ईरानी आउटलेट्स ने वेस्टर्न मीडिया की उन रिपोर्टों की ओर भी इशारा किया जिनमें अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइल स्टॉक में बढ़ती कमी को हाईलाइट किया गया था, जिसमें सेमी-ऑफिशियल न्यूज एजेंसी तस्नीम ने इस कमी को ईरान पर हमला रोकने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के पीछे मुख्य वजहों में से एक बताया. तेहरान के विरोध के बावजूद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों ने हमसे अभी-अभी किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है. यह डिप्लोमैटिक बातचीत पांच महीने से ज़्यादा समय तक चली मिलिट्री बातचीत के बाद हुई है, जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, जब अमेरिका और इजराइली सेना ने तेहरान पर हमले शुरू किए थे, और इसका कोई साफ हल नहीं दिख रहा था. पहले का सीजफायर फ्रेमवर्क, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना भी शामिल था, टूट गया. इससे ईरान ने हाल के हफ़्तों में दोनों देशों के बीच हमले फिर से शुरू होने पर इस जरूरी समुद्री रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. फार्स ने ईरानी बातचीत करने वालों के एक करीबी सोर्स के हवाले से बताया कि होर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा।

ओमान तट पर मालवाहक जहाज पर अज्ञात हमला : जांच शुरू

लंदन । यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने घोषणा की कि ओमान के अल-खसाब से करीब 20 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में एक मालवाहक जहाज अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकरा गया। यूकेएमटीओ को संकट कॉल के माध्यम से घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हमला तब हुआ है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ईरान के साथ चल रही वार्ताओं पर की गई टिप्पणियों के ठीक बाद। ट्रम्प ने कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमले को टाल दिया था। राष्ट्रपति ट्रम्प ने वार्ताओं का जिक्र कर ईरान के लिए आखिरी मौका बताया था ताकि वे एक अच्छा दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकें। उन्होंने दावा किया कि बातचीत ईरान के अनुरोध पर हो रही थी और दोहराया कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वाशिंगटन का प्राथमिक उद्देश्य बना हुआ है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के संबंध में चल रही चर्चाओं का भी उल्लेख किया था। हालांकि, उनकी टिप्पणियों के तुरंत बाद, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वार्ताओं की रिपोर्टों को सिरे से खारिज किया। बघेई ने स्पष्ट किया कि तेहरान वाशिंगटन के साथ किसी भी द्विपक्षीय वार्ता में शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से एक नए समुद्री यातायात मार्ग पर बनी समझ केवल सुरक्षित जहाज आवाजाही के लिए एक तकनीकी व्यवस्था थी, न कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोलने का संकेत। मालवाहक जहाज पर हुए कथित हमले ने क्षेत्रीय सुरक्षा और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य में नौपरिवहन पर चल रहे राजनयिक प्रयासों के बीच एक नई जटिलता पैदा कर दी है।

होर्मुज़ पर अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं, ओमान से बातचीत प्रगति पर

-ट्रंप का दावा- ईरानी नेता निजी और गुप्त रूप से बातचीत करने के इच्छुक हैं

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी नेता निजी और गुप्त रूप से बातचीत करने के इच्छुक दिखते हैं, लेकिन खुले तौरा पर बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान बहुत ज्यादा दोहरा चरित्र वाला रवैया अपना रहा है। वहीं, ईरान अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करने से सख्ती से इनकार कर रहा है और कहा है, हम ट्रंप से किसी तरह की बात नहीं करेंगे। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप पर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका में ही बड़े आरोप लग रहे हैं और विरोध हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा कि होर्मुज़ को लेकर ओमान के साथ बातचीत में प्रगति हो रही है, साथ ही, कतर और पाकिस्तान समेत क्षेत्रीय मध्यस्थ पर्दे के पीछे सक्रिय हैं, जो यह संकेत देता है कि सैन्य तनाव के बावजूद राजनयिक रास्ते अभी भी खुले हैं। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि ओमान के साथ बातचीत जहाजों के लिए एक अस्थायी रास्ता बनाने पर केंद्रित है, जिसमें जलमार्ग में ईरानी और ओमानी दोनों रास्तों को मिला दिया जाएगा, जब तक कि इस पर कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता। जलमार्ग से एक ही, भले ही अस्थायी, रास्ता बनाना ईरान और अमेरिका के बीच विश्वास बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस समय होर्मुज़ को लेकर अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है।

ईरान ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सैन्य प्रतिरोधक क्षमता बरकरार है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) ने घोषणा की है कि वह किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी सेना होर्मुज़ में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के मिलिट्री एडवाइज़र मोहसेन रेज़ाई ने ईरानी बंदरगाहों पर जारी नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है। रेज़ाई ने एक्स पर लिखा कि अगर नाकेबंदी जारी रही, तो अमेरिकी जहाजों और सेना को गंभीर खतरों और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को अपना व्यवहार बदलना होगा, वरना हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम होर्मुज में दूसरा कॉरिडोर खोलने की इजाज़त कभी नहीं देंगे।

वहीं अमेरिकी सीनेट में माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप तेल उद्योग से जुड़े अपने कैंपेन डोनर्स को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि आम नागरिकों को ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। शूमर ने एक्स पर लिखा- ईरान में ट्रंप का गैर-कानूनी युद्ध उनके बिग ऑयल वाले दोस्तों के लिए एक तोहफा है, जिन्होंने मुनाफा कमाने के वादे के साथ उनके कैंपेन को फंड किया था। पता चला कि यह वही वादा है जिसे उन्होंने असल में पूरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का कहना है कि यह गठबंधन बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री आवाजाही, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा शिपमेंट को सुरक्षित करेगा। रियाद में 43 देशों और ईयू की बैठक के बाद गुरुवार को इसने अपनी योजनाओं का खुलासा किया। इसने कहा कि तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जिबूती समेत 14 देशों ने प्रस्तावित गठबंधन का समर्थन किया है। खाड़ी के छह अरब देशों में से ओमान और यूएई का नाम गठबंधन का समर्थन करने वालों में शामिल नहीं था।

चीन की हरकतों से परेशान थाईलैंड को भाया भारत का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में जुटा बैंकॉक

बैंकॉक, एजेंसी। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दुनिया भर में अपनी धाक जमाती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दक्षिण एशियाई और मिडिल ईस्ट के देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस के बाद अब थाईलैंड भी इस खतरनाक मिसाइल को खरीदने की तैयारी में है। समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने और अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए थाईलैंड अब ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखा रहा है। इस मिसाइल के थाइलैंड की नौसेना शामिल हो जाने के बाद ?समुद्र में उसकी ताकत में इजाफा होगा। मिसाइल में जबरदस्त रफ्तार के साथ सटीक निशाना लगाने

की क्षमता है। इससे समुद्र में थाईलैंड की नौसेना और ताकतवर हो जाएगी और वह अपने व्यापारिक रास्तों के साथ-साथ समुद्री इलाकों को भी बेहतर तरीके से सुरक्षित कर पाएगा। बेहद खास है थाईलैंड का यह कदम थाईलैंड हमेशा से किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहने की नीति पर रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका-चीन में चल रहे तनाव को देखते हुए थाईलैंड, भारत की सहायता से अपनी रक्षात्मक स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। चीन के साथ थाईलैंड के व्यापारिक और आर्थिक संबंध अच्छे रहे हैं। पहले वो चीन से हथियार भी खरीद चुका है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागीरी और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए वो अत्याधुनिक तकनीक के लिए भारत जैसे अन्य विकल्पों को रक्षा साझेदार बना रहा है। चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में दावा करने के बाद दक्षिण एशियाई देश भारत जैसे मजबूत और विश्वस्त साझेदार बना रहे हैं। इंडोनेशिया दौरे में भी हुआ था समझौता पीएम मोदी के पिछले महीने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और एयर-टू-एयर मिसाइल सहयोग समझौता हुआ था। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में तटीय निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण और खोज एवं बचाव जैसे कई अहम क्षेत्रों में भी पूरी सहमति बनी। दोनों देशों ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए एक साथ मिलकर काम करने का बड़ा फैसला किया था।

पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर करो, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग; सड़कों पर उतरे लोग

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज हो रही है। यह मुद्दा केवल संगठनों और प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आम लोग अपने जनप्रतिनिधियों से भी सीधे जवाब मांग रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सांसदों का घेराव कर उनसे हिन्दू समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों के पक्ष में खुलकर बोलने की मांग की जा रही है।

सांसद के सामने विरोध : सिरहा जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद बबलू गुप्ता को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि उन्होंने परिवर्तन और नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाने की उम्मीद के साथ अपने जनप्रतिनिधियों का समर्थन किया था, लेकिन अब उनकी अपेक्षाओं की अनदेखी की जा रही है।

ठंडी हुई सांप्रदायिक हिंसा की आंच : नेपाल में 26 जुलाई की रात से शुरू हुई हिंसा की आंच अब मंद पड़ चुकी है। कई जिलों में बने तनाव के हालात अब काबू में हैं। हालांकि, इस घटना के बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने सरकार को 15 सूत्री मांगपत्र सौंपते हुए नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने समेत कई बड़े फैसले लेने की मांग की है। मांगपत्र में सुनसरी जिले के देवानगंज में हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच, घटना के दोषियों एवं साजिशकर्ताओं की शीघ्र गिरफ्तारी तथा जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है। साथ ही गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों की पहचान उजागर कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग रखी गई है। प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मांगपत्र में घटना में जान गंवाने वाले लोगों को शहीद का दर्जा देने, उनके परिजनों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने तथा घायलों का निशुल्क और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करने की भी मांगें शामिल हैं। साथ ही नेपाल को बौद्ध एवं किरात परंपराओं के सम्मान के साथ 'वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र' के रूप में पुनःस्थापित करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। संगठनों ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने, सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने तथा वर्ष 1990 के बाद जारी नेपाली नागरिकताओं की जांच कराने की मांग भी उठाई है।

क्या बोले पीएम बालेन शाह : पीएम बालेन शाह का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बहाली के साथ राजशाही का मुद्दा भी जुड़ता है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार फेडरल व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और मजबूती से इसका पालन करेगी। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से संघीय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी।

पाकिस्तान में बस दुर्घटना, 13 लोग घायल और बुनियादी ढांचे पर सवाल

इस्लामाबाद , एजेंसी। पाकिस्तान भर में लगातार बुनियादी ढांचे की खामियों, नागरिक कुप्रबंधन और बढ़ते सार्वजनिक सुरक्षा जोखिमों को उजागर करते हुए, सरगोधा में सड़क दुर्घटनाओं, ढांचागत विफलताओं और शहरी बाढ़ की घटनाओं की एक श्रृंखला देखी गई है, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया है।

बहेरा के पास एम2 मोटरवे पर भीषण बस दुर्घटना : बहेरा इंटरचेंज के पास एम2 मोटरवे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना में, तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे टायर बदलने के लिए खड़ी एक वाहन से टकरा गई, जिससे यात्री बस पलट गई।

शनिवार को 13 लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें राईस, मुख्तार, मुहम्मद सामी, फैजान इजाज, अली वारिस, कमर जुल्फिकार, महमूद हसन, तसावुर इजाज, नदीम, जहीर अहमद, उस्मान अली, शोएब और मुहम्मद इक़बाल शामिल हैं, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया है। रेस्क्यू 1122 के कर्मियों ने पांच गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधा में ले जाने से पहले प्रारंभिक आपातकालीन देखभाल प्रदान की, जबकि स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

सरगोधा में बुनियादी ढांचे की विफलताएं : सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में गंभीर प्रशासनिक चूक और भ्रष्ट आचरण को उजागर करते हुए, सरगोधा के उपायुक्त ने शहर के बाजार सौंदर्यीकरण अभियान में घटिया सामग्री और त्रुटिपूर्ण निष्पादन के संबंध में गंभीर चिंता जताई, जहां मानसून की बारिश के बाद नव-बिछाई गई फुटपाथ ढह गई और तूफान के पानी से दुकानों के बेसमेंट में बाढ़ आ गई। डॉन के अनुसार, उपायुक्त कार्यालय के आधिकारिक प्रतिनिधियों ने दावा किया कि कदाचार के संबंध में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए शहरी नियोजन में संरचनात्मक दोषों को दूर करने का वचन दिया।

बाढ़ और आवास सुरक्षा चिंताएं : इस बीच, सरगोधा डिवीजन के आयुक्त हाफिज शौकत अली, नगरपालिका,

राजमार्ग और जल स्वच्छता नेतृत्व सहित क्षेत्रीय प्रशासकों ने विभिन्न नगरपालिका स्थलों का निरीक्षण किया, जीर्ण-शीर्ण सड़क नेटवर्क, विफल जल निकासी बुनियादी ढांचे और उपेक्षित नागरिक उपयोगिताओं की समीक्षा की।

आयुक्त ने सिल्लवाली डिस्पोजल स्टेशन, ईदगाह डिस्पोजल स्टेशन, सिटी रोड और शहीन चौक में चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, फील्ड अधिकारियों को टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, जबकि भारी वर्षा के दौरान शहरी पक्षाघात को रोकने के लिए जल प्रबंधन एजेंसियों को चालू डिस्पोजल पंप बनाए रखने का निर्देश दिया।

आवास सुरक्षा कमजोरियों को उजागर करने वाली एक अन्य घटना में, मुरादाबाद कॉलोनी गली 12 में अपने आवास की छत गिरने से 18 वर्षीय समीन अशरफ और 20 वर्षीय फरवा अशरफ गंभीर रूप से घायल हो गए, जो भारी बारिश के बाद आधी रात को ढह गई। पारंपरिक टीआर गर्डर से निर्मित संरचना अचानक ढह गई, जिससे दोनों पीड़ित भारी मलबे के नीचे दब गए, इससे पहले कि उन्हें निकाला गया और एक निजी चिकित्सा केंद्र ले जाया गया।

बढ़ती जलवायु भेद्यता और कमजोर आपदा निवारण उपायों को और इंगित करते हुए, चेनाब और झेलम नदियों के बढ़ते जल स्तर ने आसपास के किनारों पर बाढ़ ला दी, जिससे कृषि भूमि नष्ट हो गई और ग्रामीण आबादी को खतरा पैदा हो गया, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया है।

आपातकालीन टीमों ने लगभग तीन दर्जन निवासियों को जलमग्न क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित निकाला, जबकि स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया कि अंतर-एजेंसी तत्परता को बढ़ावा देने के लिए पहले मॉक बाढ़ अभ्यास आयोजित किए गए थे।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल हर्ष फायरिंग के लिए नहीं कर सकते : हाईकोर्ट

प्रयागराज(एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल विवाह समारोहों या धार्मिक आयोजनों में हर्ष फायरिंग के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक लाइसेंसधारक का दायित्व है कि वह खरीदे और इस्तेमाल किए गए गोला-बारूद का रिकॉर्ड भी रखे। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अखिलेश कुमार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने 767 कारतूसों का हिसाब नहीं दे पाने के बाद रद्द किए गए शस्त्र लाइसेंस के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 29 जुलाई को दिए फैसले में कहा कि शस्त्र लाइसेंस एक विशेषाधिकार है, जो कानून और लाइसेंस की शर्तों के कड़ाई से पालन पर निर्भर करता है। कोर्ट ने लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस एक विशेषाधिकार है और इसे इस विश्वास के साथ जारी किया जाता है कि लाइसेंसधारक इसकी सभी शर्तों का पालन करेगा। मामले के मुताबिक याचिकाकर्ता को 2000 में शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। 2019 में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उससे खरीदे और इस्तेमाल किए गए कारतूसों का विवरण मांगा। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने सालों में 857 कारतूस खरीदे थे लेकिन वह केवल 57 कारतूस और 33 खोखे ही प्रस्तुत कर सका।

मेरठ में कांवड़ियों के दो गुट आपस में भिड़े, चले लात-घूसे और डंडे, क्षेत्र में फैला तनाव

मेरठ। मेरठ में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर सोमवार को दो बाइक सवारों के बीच हुई टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते कांवड़ियों के दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लात-घूंसे और लाठियां एक-दूसरे पर बरसाईं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। वीडियो फुटेज में थप्पड़ मारते, लातों-घूंसे बरसाते और डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं। इस बीच मेरठ पुलिस ने कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमले के वायरल दावों का खंडन किया। मेरठ पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिसकर्मियों की पिटाई या उनके कपड़े फाड़ने जैसी बातें सच नहीं हैं। वीडियो में दिख रहा सोनू नाम का युवक बाइक से जा रहा था और उसकी बाइक हरिद्वार से जल लेकर आ रहे एक कांवड़िये की बाइक से टकरा गई, जिससे विवाद हो गया। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति की मेडिकल जांच कराई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के एसपी सिटी के मुताबिक कांवड़ियों की दो बाइकों के आपस में टकराने के कारण विवाद हुआ था। झड़प की सूचना मिलने पर सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। बता दें सालाना कांवड़ यात्रा के कारण गाजियाबाद में स्कूल और कॉलेज 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑर्डर में कहा गया कि इसी तरह जिले में चलने वाले सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टिट्यूट भी 4 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि, किसी भी कोर्स या सब्जेक्ट के लिए पहले से तय एग्जाम तय समय के अनुसार होते रहेंगे। इस ऑर्डर का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

मणिपुर में एक उग्रवादी गिरफ्तार, अभियान में भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद

इंफाल(एजेंसी)। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के काकचिंग शहर में एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े 42 साल के उग्रवादी को गिरफ्तार किया जबकि कांगपोकपी जिले में एक अलग अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है। मंगलवार को पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि प्रतिबंधित संगठन कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (अपुनबा) के स्वयंभू 'मेजर' को सोमवार को वांगू मामेइचिंग इलाके में उसके घर से पकड़ा। बयान में कहा गया है कि उसी दिन एक अलग अभियान में, सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी के सैकुल पुलिस थाना क्षेत्र में मकोकचिंग जंगल की पहाड़ी श्रृंखला में हथियार और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने बताया कि बरामद हथियारों में एक एम16 राइफल, सात पिस्तौल, एक मार्क-3 राइफल, एक स्नाइपर राइफल, एक .22 बोल्ट-एक्शन गन, 25 सिंगल-बैरल बंदूकें, अलग-अलग कैलिबर के 76 कारतूस, चार पंपी, तीन हथगोले और बीस डेटोनेटर शामिल हैं। अभियान के दौरान चार रेडियो सेट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी पाबंदी 15 तक बढ़ाई

-गोवा सरकार से अनुरोध कर मांगा सहयोग, सीएम सांवत ने दिया आश्वासन

मुंबई(एजेंसी)। समुद्री मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर लगी पाबंदी को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने गोवा के सीएम डॉ. प्रमोद सावंत से फोन पर बात कर साझा की। राणे ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने गोवा के सीएम सावंत से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने उन्हें महाराष्ट्र के मत्स्य विभाग द्वारा 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में बताया।

इस दौरान उन्होंने गोवा सरकार से अनुरोध किया कि इस अवधि में महाराष्ट्र का सहयोग करे और यह तय करे कि गोवा के मछुआरे महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए ना आएं। मंत्री राणे ने कहा कि सीएम सावंत ने इस मामले पर सकारात्मक जवाब दिया और पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। राणे ने सहयोग के लिए सीएम सावंत का धन्यवाद भी किया। बता दें महाराष्ट्र सरकार ने तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके तहत राज्य की तटरेखा से 12 समुद्री मील यानी करीब 24 किलोमीटर के भीतर व्यावसायिक और यंत्रीकृत मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। यह पाबंदी केंद्र सरकार के 31 जुलाई को खत्म हुए मानक प्रतिबंध से भी आगे तक बढ़ाई गई है। हालांकि इस प्रतिबंध से पारंपरिक मछुआरों को छूट दी गई है। अधिकृत छोटे और बिना मोटर वाले नावों का इस्तेमाल करने वाले पारंपरिक मछुआरे तट के पास स्थानीय पानी में मछली पकड़ सकते हैं।

वहीं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए यंत्रीकृत नावों को 1 अगस्त से 12 समुद्री मील से आगे खुले समुद्र में मछली पकड़ने की इजाजत है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस पाबंदी का मकसद समुद्री जीवों को प्रजनन का समय देना और मछली भंडार को बढ़ाना है ताकि मछुआरों को आगे चलकर बेहतर मुनाफा मिल सके।

मुंबई में जेन जी और जेनरेशन अल्फा से संवाद करेंगे मोहन भागवत

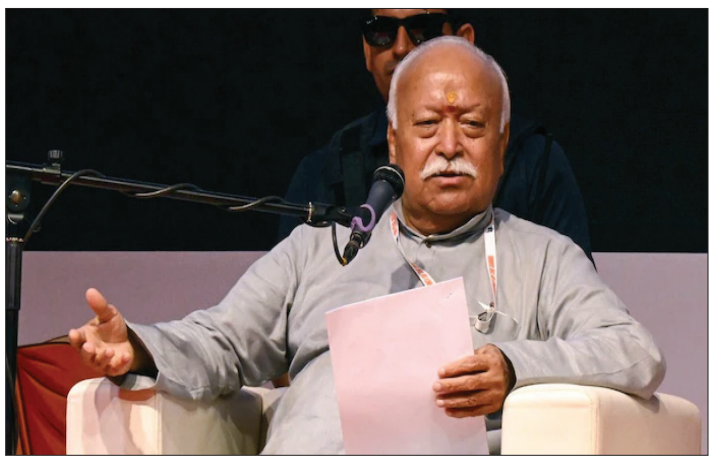

मुंबई (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई में जेन जी और जेनरेशन अल्फा के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस'(आईआईएमयूएन) के 15वें सालाना चैंपियनशिप सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 100 से ज्यादा शहरों से 15 से 19 वर्ष की आयु के 2,000 से अधिक हाईस्कूल छात्र हिस्सा लेंगे।

इस सम्मेलन की थीम 'दुनिया को एकजुट करने में युवाओं की भूमिका- भारतीय तरीका रखी गई है। कार्यक्रम में युवा नेता स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भागवत का संबोधन सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत करेगा, जिसके बाद छात्रों के नेतृत्व में कई दिनों तक बहस और नीतिगत चर्चाओं का आयोजन होगा। आईआईएमयूएन के संस्थापक ऋषभ शाह ने कहा कि नेतृत्व का अर्थ केवल अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करना नहीं, बल्कि उनकी बातों को सुनना भी है। उन्होंने कहा कि देश की बदलती परिस्थितियों में युवाओं के साथ संवाद की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है।

भागवत इससे पहले भी जेनरेशन जी के व्यवहार, सोच और चुनौतियों पर अपने विचार रख चुके हैं। उन्होंने युवाओं को स्वाभाविक रूप से अच्छा, बदलाव के लिए तैयार और संवेदनशील बताया, लेकिन यह भी कहा कि कई बार वे बिना पर्याप्त विचार के भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने युवाओं के साथ परिवारों में संवाद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि केवल आदेश देने की व्यवस्था अब प्रभावी नहीं रह गई है। परिवारों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों के साथ बातचीत के जरिए सहमति बनाने का प्रयास करें। उन्होंने डिजिटल जीवनशैली और मोबाइल की बढ़ती निर्भरता पर भी चिंता जताई। भागवत ने कहा कि अभिभावकों को बच्चों को सलाह देने से पहले खुद सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम के इस्तेमाल में अनुशासन अपनाना चाहिए। भागवत का यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं की भागीदारी जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। हाल में नीट परीक्षा से जुड़े विवादों को लेकर छात्रों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे। इसके बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार और भरोसा बहाल करने की मांग तेज हुई थी। युवाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल में अपील की थी कि गुस्से के बजाय संवाद और मार्गदर्शन का रास्ता अपनाया जाए। उन्होंने कहा था कि भटके हुए युवाओं को समझाने और सही दिशा देने की जरूरत है। मुंबई में होने वाली भागवत की बातचीत को भी युवाओं की सोच, आकांक्षाओं और चुनौतियों को समझने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

चुनाव नतीजों पर बोले नितिन नवीन- हार से सीखेंगे, जनता के बीच जाएंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, कि हमारी पार्टी जनादेश का सम्मान करती है। उन्होंने गुजरात की मांजलपुर सीट पर जीत के लिए

मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, जबकि बांकीपुर और दतिया में मिली हार पर गंभीर आत्ममंथन का भरोसा दिलाया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मांजलपुर की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है, जिसके लिए पार्टी उनके प्रति आभारी है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर और दतिया में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, इसलिए पार्टी इन दोनों सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा करेगी और नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाकर विश्वास मजबूत करेगी। गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा के सतेन्द्रभाई पटेल ने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 30,630 मतों से हराया। इससे हटकर बिहार की बांकीपुर सीट उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को 19,324 मतों से पराजित किया है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों से पराजित कर इतिहास रचने जैसा कार्य कर दिखाया है। भाजपा नेतृत्व ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और पार्टी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी।

मोदी सरकार की आर्थिक और रोजगार नीतियों ने जॉब मार्केट को गहरे संकट में धकेला

-कांग्रेस नेता जयराम ने भर्तियों में आई कमी को लेकर सरकार को घेरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने बड़ी निजी कंपनियों में नई भर्तियों में आई कमी के दावे वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार की आर्थिक और रोजगार नीतियों ने देश के जॉब मार्केट को गहरे संकट में धकेल दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश का युवा अब केवल प्रचार या रील से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि उसे रोजगार चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं के रोजगार संकट का समाधान खोजने के बजाय हेडलाइन मैनेजमेंट और ध्यान भटकाने की राजनीति में लगी हुई है।

एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में देश की शीर्ष 11 कंपनियों में से नौ में नई नौकरियों में 27 फीसदी की गिरावट आई है। उनके मुताबिक यह स्थिति बताती है कि देश गंभीर रोजगार संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार समाधान तलाशने के बजाय समस्या के अस्तित्व से ही इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट समस्या के सिर्फ ऊपरी हिस्से को दर्शा रही है।

जयराम रमेश ने दावा किया कि यदि बड़ी कंपनियों में यह स्थिति है तो मोदी सरकार की नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की हालत का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक और रोजगार नीतियों ने पूरे देश के 'जॉब मार्केट' को गहरे संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आज युवाओं के रोजगार संकट का समाधान खोजने के बजाय केवल हेडलाइन मैनेजमेंट और ध्यान भटकाने की राजनीति में लगी हुई है। रमेश ने कहा कि देश का युवा समझदार है और उसे खुश करने के लिए रील नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे।

संबित पात्रा ने मढ़ा संसद नहीं चलने देने का विपक्ष पर आरोप

-जेपीएससी परीक्षा पर कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार चल रहे गतिरोध को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी भी विषय पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार नहीं है और लगातार शोर-शराबा कर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।

भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि संसद का प्रत्येक सत्र करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन से संचालित होता है, लेकिन मानसून सत्र शुरू होने के बाद से प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसी महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। उनका आरोप था कि विपक्ष की रणनीति केवल व्यवधान उत्पन्न करने की है, जिससे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। यहां पर भाजपा सांसद ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड में हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक इस विषय को सदन में उठाने से बच रहे हैं और विपक्ष की यह चुप्पी उसके चयनात्मक आक्रोश को दर्शाती है।

कर्नाटक मामले में राहुल गांधी चुप क्यों?

संबित पात्रा ने कर्नाटक में पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती और कथित पेपर लीक के विरोध में छात्रों के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने छात्रों के आंदोलन को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की और कहा कि पहले छात्रों को भूख हड़ताल करने दें, फिर लाठीचार्ज होगा और उसके बाद ही इस्तीफे पर विचार करेंगे। पात्रा ने आरोप लगाया कि इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि संसद में लगातार नैतिकता की बात की जाती है।

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक, 2026 जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा नहीं हो सकी। उनके अनुसार ये ऐसे विधेयक हैं जिनका सीधा संबंध आम नागरिकों के अधिकारों और बैंकिंग व्यवस्था से है, लेकिन संसद में व्यवधान के कारण जनता इनके प्रावधानों से अवगत नहीं हो पा रही है। इसी के साथ ही संबित पात्रा ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करने और महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा में भाग लेने की अपील की।

जीत के बाद बोले पीके- बिहार को शिक्षा, रोजगार और विकास केंद्रित नेतृत्व चाहिए

-बांकीपुर सीट जीतने के बाद प्रशांत किशोर का भाजपा पर हमला

पटना (एजेंसी)। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम बिहार की राजनीति के लिए बड़ा संदेश है और राज्य को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसी मूल समस्याओं के समाधान पर काम करे।

प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि बिहार के भविष्य के लिए है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भाजपा को सलाह देते हुए कहा कि बिहार में बेहतर नेतृत्व सामने लाने की जरूरत है और बांकीपुर की जनता ने स्पष्ट संकेत दिया है। उधर, भाजपा की हार पर जदयू नेता श्याम रजक ने भी एनडीए को आत्ममंथन की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि बांकीपुर एनडीए का मजबूत गढ़ माना जाता था, इसलिए इस हार की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। रजक के अनुसार, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और बाहरी नेताओं को प्राथमिकता देना हार का प्रमुख कारण रहा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए अपने पारंपरिक दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सका। श्याम रजक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद पूरी निष्ठा से पार्टी प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकता है।

दीपके पर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप, गिरफ्तारी की मांग

-शिकायत में बताया पाकिस्तानी एजेंट

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दीपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। शिकायत में दीपके पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिकायत में अभिजीत दीपके को पाकिस्तानी एजेंट और उमर खालिद का समर्थक बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

फैजान अंसारी ने डीसीपी कार्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में दावा किया कि दीपके के समर्थकों ने उन पर दो बार हमला किया है। उनके अनुसार, ये हमले पुणे और औरंगाबाद में हुए, जिनके संबंध में उन्होंने स्थानीय स्तर पर पहले ही मामले दर्ज करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के सबूत उनके पास मौजूद हैं और इसी आधार पर वह शिकायत लेकर मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। शिकायत में अभिजीत दीपके को पाकिस्तानी एजेंट और उमर खालिद का समर्थक बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान कुछ फिल्मी हस्तियों को पैसे देकर बुलाया गया था। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण पेश नहीं किया गया है।

फैजान अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ चर्चित हस्तियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए भुगतान किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उर्फी जावेद को एक लाख रुपये और पूनम पांडे को 20 हजार रुपये दिए गए थे। इन दावों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि अभिजीत दीपके देश का माहौल खराब कर रहे हैं और यदि उनके खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने पुलिस से तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। गौरतलब है कि सीजेपी के बैनर तले जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय तक आंदोलन चला था, जिसमें कई चर्चित हस्तियां भी शामिल हुई थीं। फिलहाल, शिकायत में लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ता के दावे हैं और उनकी सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले में अब दिल्ली पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

तृषा पर अभद्र टिप्पणी मामले में पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को किया गिरफ्तार

-डीएमके ने कार्रवाई को राजनीतिक बताया तो समर्थकों ने रोड किया जाम

-टीवीके और भाजपा ने गिरफ्तारी का किया स्वागत

चेन्नई (एजेंसी)। अभिनेत्री तृषा को लेकर कथित अभद्र और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं डीएमके नेता तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उनके चेन्नई स्थित आवास पहुंची थी, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। इस कार्रवाई के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और ईसीआर रोड पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया।

स्टालिन को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने मीडिया को बताया, तंजावुर में आयोजित एक विरोध सभा के दौरान उदयनिधि स्टालिन की कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। चेन्नई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्रन नायर ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की। विवाद की शुरुआत कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक रैली से हुई, जहां उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे। भाषण के दौरान भीड़ से तृषा-तृषा के नारे लगे, जिस पर उदयनिधि की प्रतिक्रिया को विपक्षी दलों ने अभिनेत्री के प्रति अपमानजनक और महिलाओं का सम्मान घटाने वाली टिप्पणी बताया। इसके बाद मामला तेजी से राजनीतिक विवाद में बदल गया।

सीमा पार से हो रही नशीली दवाओं की तस्करी, एन्क्रिप्टेड ऐप्स का बढ़ा खतरा

--2021 के बाद से ड्रोन की मदद से तस्करी में तेजी देखी गई

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान से संचालित हो रहे नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क पंजाब में घुसपैठ के लिए उन्नत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्म जैसे स्क्रेड और जंगी, वर्चुअल नंबर, फर्जी केवाईसी-आधारित सिम कार्ड और जीपीएस-सक्षम ड्रोन शामिल हैं। इन तरीकों से वे सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बच निकलते हैं और पंजाब में अवैध माल की तस्करी को अंजाम देते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा नार्को-टेररिज्म और नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करने के साथ गृह मंत्रालय को पंजाब पुलिस से ड्रोन प्रयोगशालाओं की स्थापना का अनुरोध प्राप्त हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये सुविधाएं पाकिस्तान स्थित ड्रग सिंडिकेट द्वारा सीमा पार भेजे गए ड्रोन के फ्लाइट लॉग डेटा की जांच में मदद करेंगी। हाल के वर्षों में, ड्रोन-आधारित तस्करी सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर पंजाब के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है। 2021 के बाद से, ड्रोन-सहायता प्राप्त नशीली दवाओं की तस्करी में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिससे पंजाब देश का सबसे ज्यादा प्रभावित सीमावर्ती राज्य बन गया है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि अकेले 2025 में, देश भर में ड्रोन से संबंधित नशीली दवाओं की तस्करी की 305 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 298 पंजाब सीमा पर हुईं। इन घटनाओं में लगभग 460 किलोग्राम नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई। इस बरामद खेप में 448 किलोग्राम हेरोइन, नौ किलोग्राम मेथामफेटामाइन और तीन किलोग्राम अफीम शामिल थी, जो राज्य में इस उभरते खतरे की गंभीरता को दर्शाती है। सूत्रों ने बताया कि पंजाब, अंतरराष्ट्रीय सीमा से अपनी निकटता के कारण, सीमा पार तस्करी की गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। यहां नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की आपूर्ति और आतंकी वित्तपोषण का एक उभरता हुआ गठजोड़ सक्रिय है।

ड्रग सिंडिकेट भारत में पाकिस्तान की सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की अवैध आपूर्ति का समन्वय करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ये एप्लिकेशन इंटरसेप्ट करने में मुश्किल होते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस बीच, नार्को-टेररिज्म से जुड़े मामलों समेत ड्रग मामलों की जांच की निगरानी के लिए, केंद्र ने एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकी वित्तपोषण से उनके लिंक से निपटने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पंजाब में अब तक चार राज्य-स्तरीय जेसीसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन उपायों के बावजूद, उपरोक्त चुनौतियां बनी हुई हैं और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के एक मंथन सत्र के दौरान इन्हें केंद्र के समक्ष उठाया था, जिसमें पंजाब ने विशेष रूप से इन चिंताओं को उजागर किया था।